अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

वर्ष-38, अंक-1, 16-31 अगस्त, 2014

प्रकाशन का 38वां वर्ष

प्रवेशांक

पूंजी के टीले, गरीबी के गड्ढे!

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

वर्ष : 38, अंक : 01, 16-31 अगस्त, 2014

संपादक
बिमल कुमार
मो. : 9235772595

कार्यकारी संपादक
अशोक मोती
मो. : 7488387174

संपादक मंडल
डॉ. रामजी सिंह
भवानी शंकर 'कुसुम'

संपादकीय कार्यालय
सर्व सेवा संघ-प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी-221001 (उ.प्र.)
फोन : 0542-2440-385/223
ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com
sarvodayavns@yahoo.co.in
Website : sssprakashan.com

शुल्क

मूल्य	:	पांच रुपये
वार्षिक	:	100 रुपये
आजीवन	:	1000 रुपये

विज्ञापन दर

पूरा पृष्ठ	:	2000 रुपये
आधा पृष्ठ	:	1000 रुपये
चौथाई पृष्ठ	:	500 रुपये

इस अंक में...

1. अध्यक्ष का संदेश... 02
2. पूंजी का केन्द्रीकरण जारी... 03
3. पूंजी के टीले, गरीबी के... 04
4. असंवैधानिक है यह विकास... 08
5. खाद्यान्न नीलामी की वस्तु... 09
6. गहरी नींद के सपनों में... 11
7. क्या स्त्री पुरुष के समान... 12
8. फिलीस्तीन : आग का गोला... 14
9. जीवन का विज्ञान है, आयुर्वेद.. 16
10. गतिविधियां एवं समाचार... 17
11. काका कालेलकर का नमन!... 18
12. कविताएं... 20

'सर्वोदय जगत' में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। उनके साथ सर्व सेवा संघ, संपादक मंडल, संपादक या कार्यकारी संपादक का सहमत होना जरूरी नहीं है।

सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष
का

संदेश

सर्वोदय जगत का सफर, आप भी बनें, हमसफर

''यह प्रसन्नता का विषय है कि 'सर्वोदय जगत' अपनी गरिमामय यात्रा के 37वें वर्ष पूरे कर 38वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। वैसे देखा जाय तो 'सर्वोदय' सामयिकी के प्रकाशन का यह 65वां वर्ष है। इसका प्रकाशन 1949 में प्रारम्भ हुआ। पहले यह 'सर्वोदय' के नाम से प्रकाशित होता था, बाद में 'भूदान यज्ञ' और 'सर्वोदय जगत' बना। इसके संपादकों पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि सर्वोदय आंदोलन के शीर्ष नेतृत्व इसके संपादक रहे हैं। जब 'सर्वोदय' आरम्भ हुआ तब आचार्य विनोबा इसके संपादक थे, फिर दादा धर्माधिकारी संपादक बने। आगे श्री धीरेन्द्र मजूमदार, सिद्धराज ढड्ढा, आचार्य राममूर्ति, प्रभाष जोशी जैसे मनीषियों की कलम की सुगंध पाठकों तक पहुंचती रही है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ-साथ सत्य और अहिंसा पर आधारित ऐसे समाज की स्थापना करना, जिसमें जीवन मानवीय तथा लोकतांत्रिक मूल्यों से अनुप्राणित हो, जो शोषण, दमन, अनीति और अन्याय से मुक्त हो तथा जिसमें मानव-व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए पर्याप्त अवसर हो, 'सर्वोदय जगत' इन्हीं उद्देश्यों का का मशाल वाहक है।

पुराने पाठकों को यह ज्ञात होगा ही कि सर्व सेवा संघ 'सर्वोदय' के अतिरिक्त 'सर्वोदय' सामयिकी, नयी तालीम, भूदान तहरीक, भूदान (अंग्रेजी) आदि सामयिकों का भी प्रकाशन करता रहा है।

दुनिया के विभिन्न क्रांतियों का संदेश रहा है कि समाज में विषमता घटेगी और समता, बंधुता पर आधारित समाज बनेगा, पर इस उद्देश्य की पूर्ति अभी बाकी है। जब तक ये उद्देश्य पूरे नहीं होते, समाज में क्रांति के अंकुर प्रस्फुटित होते रहेंगे।

'सर्वोदय जगत' नये स्वरूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसे और समृद्ध बनाना है; यह विचारों का तो वाहक है ही, साथ ही इन विचारों की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं, उसकी झलक पाठकों को मिलनी चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब देश भर में फैले सर्वोदय के कार्यकर्ता, सर्वोदय मित्र और 'सर्वोदय जगत' के सुधी पाठकजन अपनी लेखनी और अपने क्षेत्र की हलचलों को 'सर्वोदय जगत' के लिए भेजकर सर्वोदय जगत को लाभान्वित करेंगे। जैसा कि विदित है 'सर्वोदय जगत' अहिंसक क्रांति का संदेशवाहक एक गैर-व्यावसायिक पाक्षिक है। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना सभी कार्यकर्ताओं एवं पाठकों का दायित्व है। मेरी विनम्र अपील है कि सभी पाठक कम-से-कम पांच मित्रों को इसका ग्राहक बनाकर इस यज्ञ में सहभागी बनें।

'सर्वोदय जगत' के सभी लेखकों और पाठकों को मेरी अनेकानेक शुभकामनाएं।''

(महादेव विद्रोही)

संपादकीय

पूंजी का केन्द्रीकरण जारी

केन्द्र में नयी सरकार को काम करते दो माह से अधिक हो चुके हैं। 'परिवर्तन' की आशा में तथा पुरानी सत्ता के निकम्मेपन व जन-विरोधी नीति के खिलाफ लोगों के वोट से यह सरकार सत्ता में आयी है। लेकिन अब धीरे-धीरे स्पष्ट हो रहा है कि इस सरकार के अंतर्गत भी उन्हीं नीतियों का सातत्य रहेगा, जो सन् 1991 के बाद से अपनायी जा रही हैं।

इन दो महीनों में जो घोषणाएं हुई हैं, उनसे दो बातें स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही हैं। एक तो यह कि यह सरकार भी सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। अर्थात् भारत में पूंजी को वैश्विक पूंजी के साथ अधिकाधिक एकीकृत करना इस सरकार का सर्वप्रमुख एजेण्डा है। जो घोषणाएं हुई हैं, उनसे दूसरी बात यह प्रकट हो रही है कि प्राकृतिक स्रोतों एवं संसाधनों के दोहन में किसी भी प्रकार की बाधा आती है, तो उसे त्वरित ढंग से कैसे खत्म किया जाये। प्राकृतिक स्रोतों एवं संसाधनों को कैसे वैश्विक पूंजीवादी बाजार के लिए पूरी तरह खोला जा सकता है, इस दिशा में नीतियों को लचीला बनाने का काम शुरू हो गया है।

ऐसे में अहिंसक क्रांति को आगे बढ़ाने के तथा लोकसत्ता के निर्माण के कार्य से जो लोग जुड़े हैं, उनका कार्य थोड़ा और कठिन हो जायेगा। वर्तमान सत्ता वैश्विक बाजार एवं वैश्विक पूंजीवाद के साथ अधिक सघन रूप से जुड़ना चाहती है। वैश्विक बाजार एवं वैश्विक पूंजीवाद से जुड़ने का अर्थ है, पूंजी के केन्द्रीकरण की प्रक्रिया को और तेज करना।

पूंजी के केन्द्रीकरण के लिए दो प्रक्रियाएं जरूरी हैं। एक तो यह कि लघु स्तर पर उत्पादन करने वाले उत्पादक-श्रमिक (अर्थात् जो उत्पादक भी हैं तथा उस उत्पादन के लिए अपना एवं अपने परिवार का श्रम उसमें लगाते हैं) खत्म हों तथा उत्पादक-श्रमिक को उसके सारे उत्पादन के साधनों (अर्थात् पूंजी) से अलग कर दिया जाये। इस प्रकार पूंजी यानी उत्पादन के सारे साधन पूंजीपति के हाथ में केन्द्रित हो जाये तथा उत्पादक-श्रमिक, अब श्रम बेचने वाले श्रमिक के रूप में परिवर्तित हो जाये।

पूंजी के केन्द्रीकरण की प्रक्रिया का दूसरा हिस्सा यह था कि दुनिया भर में जितने भी प्राकृतिक स्रोत एवं संसाधन हैं, उन पर पूंजीवादी सत्ता एवं बाजार का नियंत्रण हो तथा सदियों से जो परम्परागत समुदाय इन स्रोतों-संसाधनों से जुड़े थे, उन्हें इनसे बेदखल कर दिया जाये।

गांव के संदर्भ में इन प्रक्रियाओं को देखें तो हम पायेंगे कि पूंजीवाद के अंतर्गत पूंजी के केन्द्रीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप पहले गांव की उत्पादक इकाईयों को नष्ट किया गया तथा उसके बाद गांव के संसाधनों के दोहन तथा पूंजी के स्थानांतरण के माध्यम से गांव को श्री-विहीन बनाया जाने लगा। ऐसे में पूंजीवाद के अंतर्गत गांव में उत्पादन इकाईयों का विस्तार एवं नयी इकाईयों को खड़ा करने की सम्भावना खत्म होती चली गयी।

अतः यह स्पष्ट है कि पूंजी के केन्द्रीकरण की प्रक्रिया तथा ग्राम-स्वराज्य को लाने वाली प्रक्रिया परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं हैं। वर्तमान सरकार भी पूंजी के केन्द्रीकरण के पक्ष में खड़ी है, बल्कि इस प्रक्रिया को और तेज कर रही है। ऐसे में ग्राम स्वराज्य एवं शोषण-मुक्त, दोहन-मुक्त समाज बनाने की सम्भावना और धूमिल हो गयी है। पिछले दो महीनों में ही वर्तमान सरकार ने जो प्राथमिकताएं दिखायी हैं, उनसे स्पष्ट है कि वैश्विक पूंजीवाद के आगोश में पूरी तरह जाने के लिए एक के बाद एक, नीतियों को लागू करने के लिए कटिबद्ध है।

बदलती परिस्थितियों के इस आंकलन को देखते हुए, अहिंसक क्रांति के लोकसेवकों को भी अपने कार्यक्रम एवं गतिविधियों को तत्काल तेज करने की आवश्यकता है।

सबसे पहले ग्राम-समूह स्तर पर उन क्षेत्रों को पूंजी के केन्द्रीकरण की प्रक्रिया से मुक्त करने का संघर्ष शुरू करना होगा, जहां स्वायत्त एवं आत्म-निर्भर आर्थिक गतिविधियों की सम्भावना बन सकती है। कृषि, स्वास्थ्य, खाद्य एवं पोषण, वस्त्र, जल-प्रबंधन, पशुपालन एवं ऊर्जा के क्षेत्र इनमें प्रमुख हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादक-श्रमिक को पूंजी एवं श्रम की एकता बनाये रखने का माध्यम बनाया जा सकता है। स्थानीय स्रोतों एवं संसाधनों का जहां कहीं दोहन हो रहा है, वहां लोक स्वामित्व आधारित वैकल्पिक इकाईयों को खड़ा करने की शुरुआत करनी होगी।

दूसरे प्राकृतिक स्रोतों एवं संसाधनों की लूट के लिए इन्हें बाजार के अंतर्गत लाने के लिए जो भी नीतियां हैं, या आगे बनेगी, उनका प्रबल व्यापक विरोध करना होगा। विकास के नाम पर विनाशकारी नीतियों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन, पूंजी के केन्द्रीकरण के खिलाफ एक नया माहौल बना देगा।

स्वाभाविक है कि इस रचना एवं आंदोलन का सामाजिक आधार वे समुदाय होंगे जो प्राकृतिक स्रोतों व संसाधनों पर जी रहे हैं या इन पर निर्भर थे, किन्तु अब बेदखल कर दिये गये हैं। जैसे-जैसे इन समुदायों का संगठन आंदोलन एवं रचना के लिए होगा, वैसे-वैसे हम ग्राम-स्वराज्य की ओर बढ़ सकेंगे तथा पूंजी के केन्द्रीकरण की प्रक्रिया का निषेध कर सकेंगे।

बिमल कुमार

आमुख

पूंजी के टीले, गरीबी के गड्ढे

❑ महादेव विद्रोही

सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष भाई महादेव विद्रोही की नजर देश की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों पर सदैव लगी रहती है। जब भी वे कोई टिप्पणी करते हैं, तो प्रमाणिक व तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ। राजघाट, वाराणसी में उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के लोकसेवकों एवं सर्वोदय मित्रों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर 27 जुलाई, 2014 का उनका उद्घाटन संबोधन जो देश की सामाजिक, आर्थिक विषमता को प्रकट करता है, यहां प्रस्तुत है। **–का. सं.**

सर्वोदय के जो हमारे तीर्थ हैं उनमें दक्षिण भारत में तेलंगाना के पांचमपल्ली गांव और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, हमीरपुर व मंगरोठ का महत्त्व है। सर्वोदय आंदोलन के शुभारम्भ में उत्तर प्रदेश की भूमि का बड़ा योगदान रहा। आदरणीय धीरेन दा एवं महावीर भाई के 'समग्र ग्राम सेवा की ओर' जैसे अभियान तथा इसी तरह भूदान में मेवालाल गोस्वामी एवं लोकेन्द्रभाई जो अपने साथ एक नेवला लेकर चलते थे और जिन्हें लोग 'छोटे राजा' के नाम से जानते थे, ऐसे कई लोग यहां रहे हैं, जो सर्वोदय आंदोलन के रत्न रहे। कृष्णचंद्र सहाय, अर्जुन भाई, स्वामी कृष्णानंद, महावीर भाई जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला उत्तर प्रदेश सर्वोदय जमात में हैं, जिनकी भूमिका भूदान एवं चम्बल के डाकुओं के आत्मसमर्पण में काफी महत्त्वपूर्ण रही, भले वह समर्पण विनोबा या जे. पी. के नेतृत्व में ही क्यों न हुआ हो। चम्बल में निडर घूमकर दस्युओं से सम्पर्क साधने एवं संवाद के वे सशक्त सूत्र थे।

अस्तु आज के इस प्रशिक्षण शिविर में आप सबों को संबोधित कर मुझे अपार खुशी हो रही है। इस सत्र के उद्घाटन के अवसर पर 'राष्ट्रीय परिस्थितियां एवं हमारी भूमिका' विषय पर मुझे कुछ कहने की जिम्मेवारी दी है। आज की परिस्थितियों का जब भी हम आकलन करते हैं तो हम गांधी और गांधी के 'हिन्द स्वराज्य' के सूत्र वाक्य को नहीं भूल सकते।

अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज्य' में गांधी ने 'रेल' का विरोध किया। कुछ लोग जो इसके रहस्य को नहीं जानते थे वे स्वाभाविक रूप से प्रश्न करते हैं कि जो गांधी इतनी रेल यात्राएं देश और विदेश दोनों जगह कीं, वे रेल के विरोधी क्यों थे? उनके विचार विरोधाभाषी क्यों हैं? अमर्त्यसेन जो एक विश्व विख्यात अर्थशास्त्री हैं ने भी अपनी पुस्तक में रेल के महात्म्य पर प्रकाश डाला है और इस सिलसिले में 40 के दशक में पश्चिम बंगाल में हुए एक अकाल की चर्चा की है, जिसमें लगभग 10 लाख लोग कालकवलित हुए थे। उन्होंने लिखा कि उस वर्ष महज 25 प्रतिशत कृषि उत्पादन में कमी हुई थी; जिसके कारण इतनी भारी संख्या में लोगों के मरने की स्थिति नहीं बन सकती थी, क्योंकि उस साल बंगाल में अनाज का सर्वाधिक निर्यात हुआ था और सर्वाधिक लगान की भी वसूली हुई थी। रेलवे को तो समुद्र तट से अंग्रेजों ने इसलिए जोड़ा ताकि वे भारत से भारी मात्रा में कच्चा माल अपने देश सुगमता से ले जा सकें। हिन्द स्वराज्य में गांधी के रेल के विरोध का मर्म हम इससे समझ सकते हैं। इसलिए 'हिन्द स्वराज्य' दुनिया की एक नयी संस्कृति का नाम है। 'जी भर कर खाओ और हाजमोला से पचाओ' जो आज की संस्कृति बनी है का विरोध 'हिन्द स्वराज्य' में है, इस पुस्तक को बार-बार पढ़ने की जरूरत है।

बुलेट ट्रेन की जरूरत

अभी रेल बजट आया है। अहमदाबाद से मुम्बई के लिए बुलेट रेल चलाने की योजना है। 493 किमी की इस रेल परियोजना पर 122 करोड़ प्रति किलोमीटर की दर से खर्च होंगे और यह लागत जमीन और विद्युत आदि पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त है। यह काम जापान की एक कंपनी को दिया जाना है। अनुमान है कि विमान से अधिक भाड़ा इस ट्रेन के लिए लगेगा और समय भी। सवाल यह है कि भारत के जिन क्षेत्रों में अभी तक रेलवे की पहुंच नहीं है वहां रेलवे ले जाने की जरूरत है या बुलेट ट्रेन चलाने की! इसी तरह अब उद्योग लगाने के लिए प्रदूषण संबंधी प्रमाण-पत्र ऑन लाईन देने की स्वीकृति धड़ल्ले से दी जायेगी जो पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती पैदा करेगी।

गुजरात में साबरमती नदी को आधा पाट

हम राज करें, तुम राम भजो
–बेर्टोल्ट ब्रेस्ट

खाने की टेबुल पर जिनके
पकवानों की रेलमपेल
वे पाठ पढ़ाते हैं हमको
संतोष करो, संतोष करो।
उनके धंधों की खातिर
हम पेट काटकर टैक्स भरें
और नसीहत सुनते जायें–
'त्याग करो, भई त्याग करो।'
मोटी-मोटी तोंदों को जो
ठूँस-ठूँस कर भरे हुए
हम भूखो को सीख सिखाते
'सपने देखो, धीर धरो।'
बेड़ा गर्क देश का करके
हमको शिक्षा देते हैं–
तेरे बस की बात नहीं'
'हम राज करें, तुम राम भजो।'

दिया गया है और उसे दोनों ओर से घेर भी दिया गया है, जिसके निकट जाने के लिए भी आपको 10 रुपये शुल्क देने होंगे। साबरमती नदी में कोई भैंस, गाय या पशु पानी नहीं पी सकते। वहां झोपड़पट्टियां नहीं रह सकतीं, आप आखिर कैसा समाज बनाना चाहते हैं। पैसे कमाने की होड़ में गुजरात के कई गांव ऐसे हैं जहां कोई युवक नहीं हैं सिर्फ बूढ़े मां-बाप हैं और यदि उनकी मृत्यु हुई तो दाह-संस्कार के लिए बगल के दूसरे गांव से लोगों को आना पड़ता है। बांग्लादेश और भारत की सीमा पर पैसे देकर लोग एक-दूसरे देश में प्रवेश कर रहे हैं। गलत कागजात के आधार पर लोगों को विदेशों में भेजने वाली कंपनियां खूब कमा रही हैं। वी. एम. तारकुंडे ने तो यह पाया कि सीमा सुरक्षा बल के लोग 100-50 रुपये लेकर लोगों को सीमा पार कराते हैं।

कुछ समय पूर्व पश्चिम बंगाल गया था। आदिवासी महिलाओं के बीच जाने और उनसे संवाद करने का मौका मिला। मैंने पूछा—टाटा का नाम सुना है? अधिकांश को उनका नाम मालूम था। 'फेयर एवं लवली' क्रीम को भी महिलाएं जानती थीं। रिलायंस का नाम कम ही महिलाओं को मालूम था। मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में किसी व्यक्ति की प्रतिमाह कमाई क्या है तो कहा कि अधिकतम 600 रुपये प्रतिमाह। मैंने पूछा, कलक्टर का नाम सुना है—उनका वेतन कितना होगा, तो महिलाओं ने बहुत सोचकर बताया 1500 रुपये। यह आर्थिक गैर-बराबरी हमारे देश में है। मैंने इस आर्थिक गैर-बराबरी के संबंध में कई तथ्यों को संकलित किया, जिस आधार पर इस गैर-बराबरी को सही रूप में समझा जा सके।

भारत में आर्थिक विषमता की जीवन्त तस्वीर

योजना आयोग के आकलन के अनुसार शहरों में रहने वाले की अपेक्षा गांवों में रहने वाला किसी परिवार की दैनिक 26 रुपये 1 पैसे एवं शहर में रहने वाले किसी परिवार की दैनिक आय 29 रुपये 1 पैसे हैं तो वह गरीब नहीं है। गुजरात में तो और भी गजब की स्थिति है। यहां की सरकार उसे ही गरीब मानती है जिसकी दैनिक आय 16 रुपये 71 पैसे से कम है। *(संदर्भ : इंडियन एक्सप्रेस, 8.4.2012, पृष्ठ 1)*

गरीबी के गड्ढे

योजना आयोग के आकलनों का विश्लेषण करें तो भारत में मोटे तौर पर एक परिवार में पांच व्यक्ति माने गये हैं। गांव में रहने वाला एक परिवार की दैनिक आय 26 रुपये को 5 व्यक्तियों में भाग करें तो प्रति व्यक्ति 5 रुपये 20 पैसे बैठते हैं।

योजना आयोग ने 26 रुपये का विभाजन निम्नवत किया है :

	योजना आयोग का आकलन	प्रति व्यक्ति खर्च
अनाज	5.5	1.1
दाल	1.02	0.204
दूध	2.03	0.406
खाद्य तेल	1.55	0.31
सब्जी	1.95	0.39
फल	0.44	0.088
चीनी	0.70	0.14
नमक एवं मसाले	0.78	0.156
अन्य खाद्य पदार्थ	1.51	0.302
ईंधन	3.75	0.75
दवा (मासिक)	3.25	0.65

दक्षिण भारत में सन टीवी नाम की एक कंपनी है। श्री कलानिधि मारन इसके प्रबंध निदेशक एवं उनकी पत्नी श्रीमती कावेरी मारन इसके निदेशक हैं। इन दोनों के संयुक्त वार्षिक वेतन 128 करोड़ 8 लाख रुपये हैं। यह रकम कितनी होती है इसका अंदाजा लगाना आम लोगों के लिए मुश्किल है, इसलिए इसका विभाजित रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री कलानिधि मारन एवं कावेरी मारन का मासिक वेतन

10,73,33,333/-

दैनिक वेतन	35,28,767/-
प्रति घंटा वेतन	01,47,031/-
प्रति मिनट वेतन	02,450/-
प्रति सेकण्ड वेतन	40.84/-

नौकरी करने वाले किसी व्यक्ति को महीने के अंत या आरम्भ में वेतन मिलता है तो उसे वह अपनी जेब में लेकर घर लौटता है। मैं सोचने लगा कि यदि कलानिधि मारन एवं कावेरी मारन को एक वर्ष का वेतन एक साथ दे दिया जाय तो वह उनकी जेब में समायेगा या नहीं! इनके वार्षिक वेतन का भुगतान यदि 100/- के नोटों में किया जाय तो उसका वजन 8 हजार किलोग्राम से अधिक होगा और उसे ले जाने के लिए टाटा की 407 गाड़ी लानी पड़ेगी।

जिस देश में प्रति सेकण्ड 40.84 रुपये वेतन है उसी देश के आम आदमी की आय कितनी है, यह जानकर हृदय की धड़कन बंद होने लगती है। वर्ष 2004 में भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों की स्थिति के अध्ययन के लिए श्री अर्जुनसेन गुप्ता की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने 16 मई, 2006 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट के अनुसार इस देश के करीब 78 प्रतिशत कामगारों की दैनिक आय 9 से 20

रुपये के बीच है। बात आसानी से समझ में आये इसलिए हम यहां दैनिक आय 20 रुपये मान लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 20 रुपये दैनिक कमाने वाले की मासिक आय 600 रुपये एवं वार्षिक आय 7,200 रुपये हुई।

इस आंकड़े ने मुझे बहुत ही हैरान कर दिया। मैं सोचने लगा कि 20 रुपये कमाने वाला व्यक्ति कितने दिनों तक कमायेगा कि उसकी आय कलानिधि मारन एवं कावेरी मारन के एक वर्ष के वेतन के बराबर होगा। यह आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है। 20 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 1,77,777 वर्ष तक कमायेगा और 1 पैसा भी खर्च नहीं करेगा तब उसकी आमदनी कलानिधि मारन एवं कावेरी मारन के एक वर्ष के वेतन के बराबर होगी।

दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 1,77,777 वर्ष जीता हो तो फिर स्थिति क्या होगी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी 2010 के मानव विकास की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लोगों की औसत आयु 64.35 वर्ष है। यदि मोटा हिसाब निकालें तो 10 करोड़ 73 लाख 33 हजार 333 रुपये कमाने के लिए उसे इस धरती पर 2763 बार जन्म लेना होगा।

भारत के सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले लोग

एक जमाना था जब भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन रुपये 10 हजार था और नियम था कि राष्ट्रपति से अधिक वेतन किसी का नहीं होगा। इसी भारत में आज राष्ट्रपति का मासिक वेतन रुपये 1,50,000 है। प्रधानमंत्री का वेतन तथा भत्ता रुपये 1 लाख 60 हजार। कुछ अन्य लोगों के वार्षिक वेतन इस प्रकार हैं (करोड़ में) :

1. नवीन जिंदल	73.4
2. कलानिधि मारन	64.4
3. कावेरी मारन	64.4
4. सुनीत मित्तल	27.51
5. बृजमोहन मित्तल	26.75
6. पवन मुंजल	26.47
7. बी.जी. रघुपति	25.92
8. पंकज पटेल	25.00
9. सज्जन जिंदल	20.80
10. देवु भट्टाचार्य	17.31

भारत के वित्त राज्यमंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गयी जानकारी के अनुसार भारत के 8200 सर्वाधिक अमीर लोगों के पास करीब 47,250 अरब की दौलत है, जो अर्थव्यवस्था का 70 प्रतिशत है। सरकार की यह जानकारी ग्लोबल वेल्थ इन्टेलिजेन्स रेफरेन्स फर्म द्वारा कराये गये सर्वेक्षण पर आधारित है। यानी एक बादशाह हुआ तो सौ फकीर हो गये।

इन दस लोगों का कुल वार्षिक वेतन 418.77 करोड़ होता है यानी औसतन मासिक वेतन करीब 3.5 करोड़ है।

इसी तरह संसद सदस्यों के मासिक वेतन एवं भत्ते इस प्रकार हैं (हजार में) :

वेतन दैनिक भत्ता (सत्र के दौरान)	50
क्षेत्रीय सभा	01
कार्यालय भत्ता	25
टेलीफोन भत्ता	25

इसके अतिरिक्त उन्हें एक सहयोगी के साथ वातानुकूलित श्रेणी में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के सर्वाधिक वेतन वाले नेट ग्रीड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्री पी. रघुरामन हैं। इनका मासिक वेतन 10 लाख रुपये हैं। यह प्रधानमंत्री के वेतन से 10 गुना अधिक है।

मुकेश अंबानी का महल

जिस देश में लाखों लोगों को रहने के लिए अपना घर नहीं है उसी देश के धनकुबेर ने वर्ष 2008 में मुम्बई के अल्टमाउंट रोड पर अपना नया घर बनाया। घर का नाम रखा गया 'एंटीलिया'। घर की लागत 6 हजार करोड़ के आसपास बतायी जा रही है। 27 मंजिला इस इमारत की ऊंचाई 550 फीट है। सामान्य तौर पर इतनी ऊंचाई में 62 मंजिली इमारत बन जाती है। कुल क्षेत्रफल 4 लाख वर्गमीटर है। इसमें 500 बेडरूम बन सकते हैं। इस महल में मुकेश अंबानी परिवार के 6 लोग मुकेश, पत्नी नीता, तीन संतान—आकाश, इशा और अनंत तथा माता कोकिला बेन रहती हैं। उनकी सेवा के लिए हर पल 600 अनुचर उपस्थित रहते हैं।

6 लोगों के घूमने के लिए 168 कार हैं, जिनकी पार्किंग के लिए इस महल की 6 मंजिलें तथा इसकी सर्विसिंग के लिए एक मंजिल सुरक्षित रखी गयी है। यानी प्रति व्यक्ति 28 कार। परिवार के सदस्यों के मनोरंजन के लिए थियेटर है।

एक मंजिल आपातकालीन सेवाओं के लिए है। दूसरी मंजिल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है, जिसमें तरण ताल (स्वीमिंग पुल), एथलेटिक्स, जिमनास्टिक आदि की सुविधाएं हैं। छत पर 3 हेलीपैड बनाये गये हैं। 2 मंजिलें अतिथियों के लिए हैं। कुल नौ एक्सेलेटर लगाये गये हैं। इस भवन का लीविंग एरिया का कुल क्षेत्रफल 4 लाख फीट है।

71 लाख का बिजली बिल

25 नवंबर, 2010 को मुकेश अंबानी के इस घर का पहला बिजली बिल 70 लाख 69 हजार 488 रुपये का आया। कुल 6,37,240 यूनिट बिजली का इस्तेमाल हुआ। यह 7000 घंटों से अधिक बिजली की खपत के बराबर है। इस बिल ने मेरे शरीर में आग लगा दी है। मैं मानता हूं कि यह एक राष्ट्रीय अपराध है, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में भी सबों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। महाराष्ट्र में करीब 2 लाख 9 हजार (संदर्भ : इकोनोमिक टाइम्स, 19 अक्टूबर, 2006) एवं गुजरात में करीब 3 लाख 90 हजार किसान बिजली लेने की प्रतीक्षा सूची में हैं।

किसानों की आत्महत्या

कर्ज के बोझ में दब जाने के कारण 1997 से 2002 के बीच 6,38,645, 1997 से 2008 के बीच 13,42,873 किसानों ने आत्महत्या कर ली।

नेशनल क्राइम रेकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2009 तक 2 लाख 40 हजार किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। (आईबीएन-सीएनएन) अल्टरनेटिव इंटरनेशनल के अनुसार प्रत्येक 32 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है।

अंग्रेजी दैनिक 'डीएनए' में 26 अगस्त, 2006 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 8 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है।

इसमें अधिकांश किसान कपास के उत्पादक रहे हैं और ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के हैं।

3 नवंबर, 2010 की एक रिपोर्ट के अनुसार किसानों की आत्महत्या के कुछ आंकड़े तालिका क्रमांक-1 में प्रदर्शित किया गया है।

भारत के कुछ धनकुबेरों की सम्पति

भारत के कुछ धनकुबेरों की सम्पति इस प्रकार है जो इस देश में आर्थिक विषमता यानी पूंजीवाद के टीले और गरीबी की बढ़ती खाई का परिचायक है।

ये आँकड़े निःसंदेह देश की सामाजिक-आर्थिक विषमता की एक जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। ऐसी स्थिति देश में इसलिए पैदा हुई कि हमने गांधी के मार्गदर्शन को सही रूप में अपनाया नहीं। गांधी ने तो 1909 में हमें 'हिन्द स्वराज्य' के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति से उत्पन्न होने वाले खतरे से स्पष्टतया आगाह किया था। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज जो अशांति, हिंसा, आतंक और अनीति का माहौल है उससे उबरने के लिए हमें गांधी की ओर ही लौटना होगा और 'हिन्द स्वराज्य' के सूत्र वाक्य को अपनाने के लिए उसका पुनर्पाठ भी करना होगा। ❑

किसानों की आत्महत्या के कुछ आंकड़े (तालिका क्रमांक-1)

वर्ष	महाराष्ट्र	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	कुल राज्य	संपूर्ण भारत
1997	1917	1097	1832	2390	7236	13622
1998	2409	1813	1883	2278	8333	16015
1999	2423	1974	2379	2654	9430	16082
2000	3022	1525	2630	2660	9837	16603
2001	3536	1509	2505	2824	10374	16415
2002	3695	1896	2340	2578	10509	17971
2003	3836	1800	2678	2511	10825	17164
2004	4147	2666	1963	3033	11809	18241
2005	3926	2490	1883	2660	10959	17131
2006	4453	2607	1720	2858	11638	17060
2007	4238	1797	2135	2856	11026	16632
2008	3802	2105	1737	3152	10797	16196
कुल	**41404**	**23279**	**25685**	**32454**	**122823**	**199132**
औसत	**3450.33**	**1940**	**2140**	**2704.5**	**10235.3**	**16594.3**

भारत के कुछ कुबेरपतियों की सम्पत्ति (तालिका क्रमांक-2)

ग्लोबल रैंक	भारत का क्रमांक	नाम	उम्र (वर्ष)	शहर	उद्योग	विलियन डालर
9	1	मुकेश अंबानी	54	मुम्बई	रिलायंस	27.00
36	2	अजीम प्रेमजी	65	बंगलुरु	विप्रो	16.80
42	4	शशि एंड रवी रुईया	67	मुम्बई	इसार ग्रुप	15.80
56	5	सविता जिंदल एंड फेमिली	61	हिसार	स्टील	13.20
81	6	गौतम अदानी	49	अहमदाबाद	अदानी ग्रुप	10
97	7	कुमार मंगलम बिरला	44	मुम्बई	आदित्य बिरला ग्रुप	9.2
103	8	अनिल अंबानी	52	मुम्बई	अंबानी ग्रुप	8.80
110	9	सुनिल मित्तल एंड फेमिली	54	दिल्ली	भारतीय एयरटेल	8.30
130	10	आदि गोदरेज एंड फेमिली	69	मुम्बई	गोदरेज इंडस्ट्रीज	7.30
130	11	कुशल पाल सिंह	79	दिल्ली	रियल स्टेट	7.30
159	13	दिलीप अग्रवाल	55	मुम्बई	सन इंटरप्राइजेज	6.10
182	14	शिव नदार	65	दिल्ली	एचसीएल इंटरप्राइजेज	5.60
265	15	शिवंदर सिंह एंड मालविंदर सिंह	38	दिल्ली	फार्म्यसिटीकल्स	4.10
310	16	कलानिधि मारन	45	चेन्नई	सन नेटवर्क	3.50
347	17	उदय कोटक	52	मुम्बई	फाइनेंस	3.20

असंवैधानिक है यह विकास!

❑ जयंत वर्मा

भारत के संविधान के भाग चार में शासन के मूलभूत तत्त्व लिपिबद्ध हैं और राज्य को यह निर्देश है कि विधि बनाकर इन तत्त्वों को लागू किया जाय। अनुच्छेद-38(2) में स्पष्ट लिखा है कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करना राज्य का कर्तव्य है।

वर्ष 1950 में भारत का संविधान लागू होने के समय देश की लगभग 80 फीसदी आबादी कृषि और सहायक व्यवसायों में संलग्न थी। इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत प्राकृतिक संसाधन अर्थात् जल, जंगल और जमीन थे। उपनिवेश काल में ब्रिटिश हुकूमत ने जल, जंगल और जमीन को मनमाने तौर पर हड़प लेने के लिए असंख्य कानून बनाये। सन् 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून, सन् 1927 का भारतीय वन कानून आदि ऐसे ही कुछ कानून हैं।

ब्रिटिश हुकूमत से समझौते के तहत जब भारतवासियों को सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो उपनिवेशकालीन सभी कानूनों को कायम रखा गया। संविधान के सातवें संशोधन में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को यह अधिकार दिया गया था कि वे एक वर्ष की अवधि में ऐसे सभी कानूनों की समीक्षा करेंगे, जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किये गये थे।

यदि वे संविधान की प्रस्तावना, भाग-तीन और चार के प्रतिकूल पाये जाते हैं तो उन्हें संशोधित या निरस्त करने का भी उन्हें पूर्ण अधिकार था। दुर्भाग्य से तत्कालीन शासक वर्ग ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। इसकी वजह शायद यह थी कि उन्हें ब्रिटिशकालीन सभी कानून अपने वर्गहित में दिखे होंगे। इसके बाद यह मान लिया गया कि उपनिवेशकालीन सभी कानून संविधान सम्मत हैं।

संविधान में विकास को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। वर्ष 1990 के बाद भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियां अपनाई गयीं। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को विकास का पैमाना मान लिया गया। इसका अर्थ यह था कि जल, जंगल और जमीन पर आश्रित लोगों से ये संसाधन छीन कर कंपनियों के हवाले कर दिये जायं ताकि वे उनका भरपूर दोहन कर देश को विकसित बना दें।

योजना आयोग का अनुमान है कि आजादी के बाद निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण से लगभग 6 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं।

सर्वाधिक रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश घटा देने और खाद्यान्न के समर्थन मूल्य में निरंतर गिरावट के कारण खेती घाटे का सौदा बन गयी। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले 17 वर्षों में 3 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

एक ताजा अध्ययन के अनुसार प्रतिदिन दो हजार किसान खेती छोड़ रहे हैं। लोगों का गांव से शहर की ओर पलायन बढ़ता जा रहा है। संसद और विधानसभाओं में इस समस्या को लेकर चुप्पी दिखती है।

सभी राजनीतिक दल यह मान चुके हैं कि खेती-किसानी का काम श्रम केन्द्रित न होकर पूंजी केन्द्रित बनाया जाय। इसके लिए छोटे और सीमांत किसानों से खेती की भूमि हड़प कर कारपोरेट घरानों को सौंपने की ओर तेजी से कदम उठाये जा रहे हैं।

एन.डी.ए. की सरकार ने वर्ष 2000 में योजना आयोग का दृष्टिपत्र तैयार किया था, जिसके अनुसार वर्ष 2020 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान घटाकर मात्र 6 प्रतिशत कर देने की योजना है। यू. पी. ए. की सरकार और उसमें शामिल सभी राजनीतिक दलों का भी यही दृष्टिपत्र है।

संविधान के अनुच्छेद-39(क) में राज्य को निर्देश है कि वह अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। अनुच्छेद-39(ख) में राज्य को ऐसे कानून बनाने का निर्देश है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बँटे ताकि सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सध सकें।

यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश है कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो। आर्थिक भूमंडलीकरण की नीतियों के फलस्वरूप उपरोक्त सभी निर्देशों की धज्जियां उड़ाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं।

संविधान के भाग-चार के उल्लंघन में चलायी जा रही आर्थिक नीतियां प्रमाणित करती हैं कि संविधान के प्रति आस्था की शपथ लेकर विधायिका और कार्यपालिका में पदस्थ पदाधिकारी जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।

विकास के अधिकार के घोषणापत्र (1986) में विकास के तीन मानक बताये गये हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, स्वनिर्धारण और विकास के प्रतिफल में भागीदारी। भूमि अधिग्रहण संशोधन अधिनियम में इन तीनों मानकों का समावेश नहीं किया जाना विकास पीड़ितों के मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है।

जुलाई, 2013 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के प्रारूप में यह खुलासा किया गया है कि ग्रामीण भारत में खेती की जमीन खेतिहर समाज के नियंत्रण से निकलती जा रही है। भारत के एक तिहाई परिवार भूमिहीन हैं।

इतने ही परिवार भूमिहीनता के करीब पहुंच चुके हैं। अगले 20 प्रतिशत परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इस प्रकार भारत की 60 फीसदी आबादी का देश की कुल भूमि के 5 प्रतिशत पर अधिकार है जबकि 10 प्रतिशत जनसंख्या का 55

फीसदी जमीन पर नियंत्रण है।

यह भी स्पष्ट हो चुका है कि आर्थिक वृद्धि दर की टपकन का लाभ निर्धनों तक नहीं पहुंच रहा है। समाज में गरीबी और अमीरी के बीच खाई तेज गति से बढ़ रही है। ऐसी दशा में आर्थिक वृद्धि दर विकास का पैमाना नहीं बल्कि लूट का हथियार बन गया है। विकास की परियोजनाओं से उजड़ने वालों का यह सवाल अब बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है कि ''किसकी कीमत पर किसका विकास...।''

यह भी जानते हैं कि पांचवीं अनुसूची वाले जनजातीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं। वहां के खनिज, जल, वन और भूमि पर कारपोरेट घरानों की नजर है।

येन केन प्रकारेण वे इसे मिट्टी मोल हासिल करना चाहते हैं। पंचायतों के अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार के कानून 'पेसा' में ग्रामसभा की सहमति के बिना लोगों की बेदखली और भूमि का अधिग्रहण प्रतिबंधित है। समता और नियमगिरी के प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय ने पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में कारपोरेट घरानों को प्राकृतिक संसाधन सौंपने के सरकारी फैसलों को असंवैधानिक घोषित किया है।

इसके बावजूद शासक वर्ग द्वारा जगह-जगह एम. ओ. यू. के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के संसाधन कारपोरेट घरानों को सौंपने का सिलसिला जारी है।

5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में नगरीय निकायों के लिए स्वशासन का कानून बनाने, भूरिया समिति की सिफारिश पर अमल नहीं करके सरकार जनजातीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की लूट का दरवाजा खुला रखना चाहती है।

सरकार द्वारा संविधान के प्रावधानों की अवहेलना से ही जनजातीय समाज में रोश पनप रहा है। इस संबंध में राष्ट्रपति और गृहमंत्री ने भी अपने संबोधनों में राज्य सरकारों को आगाह किया है। अनेक सरकारी रिपोर्ट भी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि लूट को विकास बताने वाली राज्य सरकारें प्राकृतिक संसाधन कारपोरेट घरानों को बेच देने पर आमादा हैं।

खाद्यान्न : नीलामी की वस्तु नहीं है

❑ ओलिवर डी शट्टर

सन् 2008 में जब वैश्विक बाजारों में खाद्य सामग्री के मूल्यों में असाधारण तेजी छाई हुई थी, ठीक उसी दौरान मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के भोजन के अधिकार के विशेष दूत की भूमिका स्वीकार की। खाद्य आयात करने वाले देशों में भोजन-दंगे होने लगे थे और गरीबों में भूख और गहरी पैठ करती जा रही थी, लेकिन इस सबके बावजूद एक सुनहरी लकीर भी थी। हमारी खाद्य प्रणाली के असंतुलन जो कि पिछले चालीस वर्षों में लगातार बढ़ते जा रहे एकाएक दिखाई देने लगे थे। उस ग्रीष्म ऋतु में हमें पता चला कि वैश्विक खाद्यआपूर्ति अब हमसे कुछ ही खराब फसली मौसम दूर है और हम वैश्विक मांग की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हो जायेंगे। लेकिन इसी दौरान हमें वैश्वीकृत खाद्य प्रणाली के अन्यायकारी तर्क की झलक भी मिली और अत्यधिक व्यापक क्रय शक्ति वाला जनसमुदाय बहुत प्रभावशाली ढंग से इस सर्वकालिक अनिवार्य संसाधन की बोली लगाने में जुट गया।

खाद्य बाजार की क्रूर कार्यकुशलता : वैश्विक बाजार क्रूर कार्यकुशलता से आवश्यकता वाले वर्ग के बजाय सबसे ज्याद बोली लगाने वालों को संसाधन आवंटित कर देता है। यह साधारण सा जादू विकासशील देशों के बड़े क्षेत्रों में खेतों को कारों के ईंधन के लिए चारा उपजाने या पश्चिम में मांस की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक पशुओं के आहार की खेती की ओर मोड़ देता है। कुछ अनुमानों के अनुसार सन् 2009 व 2013 में मध्य यूरोपीय बायो ईंधन कंपनियों ने अफ्रीका में करीब 60 लाख हेक्टेयर भूमि खरीदी है। यहां ''अदृश्य भूमि'' यूरोप के पशुओं के लिए प्रोटीन की उपलब्धता हेतु सुरक्षित है। सन् 2010 में यह 2 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गई थी जो कि यूरोप की अपनी कुल कृषि योग्य भूमि का 10 प्रतिशत बैठती है। इतना ही नहीं छोटी प्रजातियों की मछलियां बजाय स्थानीय समुदाय द्वारा प्रयोग में लाये जाने के हजारों किलोमीटर दूर भेजी जा रही हैं। जहां पर धन कमाने के उद्देश्य से इन्हें अमीर उपभोक्ताओं और रईसों को बेची जा रही है।

भोजन की बर्बादी

अमीर देशों में बड़ी मात्रा में भोजन की बर्बादी होती है। एक यूरोपीय या उत्तरी अमेरिका उपभोक्ता एक वर्ष में औसतन 100 किलो तक भोजन कचड़े में फेंक देता है, क्योंकि खाने पर होने वाला खर्च उनके परिवार के खर्च का बहुत छोटा हिस्सा होता है। कुल मिलाकर अमीर उपभोक्ताओं का संसाधनों पर कब्जा बना हुआ है और उनकी जीवनशैली बिना किसी चुनौती के सतत जारी है। जबकि अन्य लोगों को अनिवार्य केलोरी तक नहीं मिल पा रही है और पर्यावरण पर जोखिम बढ़ता ही जा रहा है। वास्तव में इन बिंदुओं पर खाद्य प्रणाली आश्चर्यजनक ढंग से असफल सिद्ध हो रही है, जैसे कि करीब एक अरब लोग अभी भी भूखे हैं जबकि एक अरब चालीस करोड़ व्यक्तियों का या तो वजन ज्यादा है या वे मोटे हैं। वहीं खाद्य प्रणाली मानव निर्मित ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में करीब एक तिहाई का योगदान करती है। यह भी

अनुमान है कि मवेशी क्षेत्र की वैश्विक ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि इसमें मवेशियों के सांस लेने और पशु चराई हेतु वनों एवं लकड़ियों की कटाई और चारे की फसल को गिना ही नहीं गया है। इसके बावजूद अनेक लोगों का विश्वास है कि भविष्य के लिए मुख्य चुनौती वैश्विक खाद्य उत्पादन में वृद्धि ही है और बाजार के संकेतों और आपूर्ति में वृद्धि हेतु इसे और अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए।

लेकिन इससे उत्पन्न हो रही समस्याओं की अनदेखी की जा रही है व वर्तमान असफलताओं की ओर से आंख मूदी जा रही है। इसी के साथ खादों की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कारखाना खेती को अतिरिक्त महत्त्व दिया जा रहा है। हमें 21वीं सदी के लिए नये वैकल्पिक मानदंड तैयार करने की आवश्यकता है। विकासशील देश स्वमेव अपने छोटे किसानों को ऋण, तकनीक व बाजार में पहुंच संबंधी उनकी आवश्यकताओं को लेकर बहुत कुछ नहीं कर पायेंगे। पर्यावरणीय दृष्टि से सुस्थिर एवं अधिक उपज देने वाले कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और इन उत्पादकों को स्थानीय उपभोक्ताओं से जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए।

बहरहाल इन सुधारों को किसी शून्य में नहीं खड़ा किया जा सकता। हमारी वैश्विकृत खाद्यप्रणाली में सभी संकेत तो अमीर देशों के पिटारे में बंद हैं। वैश्विक दक्षिण के सुधारों की सफलता की कुंजी वैश्विक उत्तर के सुधारों में छिपी है। डेरी उत्पादों एवं जैविक ईंधन की अपनी बढ़ती मांग में कमी लाकर व खाद्य सामग्री की बर्बादी रोककर अमीर देश उनके द्वारा विश्वभर के खेतों पर लगे कलंक को धो सकते हैं और कम क्रयशक्ति वालों को उन संसाधनों के इस्तेमाल का हक दे सकते हैं, जिनकी कि उन्हें जरूरत है।

अमीर देशों की कृषि सब्सिडी गरीबों पर आक्रमण है

परिवर्तन तो आपूर्ति पक्ष की ओर से आना चाहिए। सवाल सिर्फ कितना उत्पादन कर रहे हैं का नहीं है बल्कि कैसे कर रहे

हैं का भी है। अमीर देशों में अनाज पर मिल रही अनापशनाप सब्सिडी की वजह से हाल के दशकों में मांस एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की चांदी हो गई है। इसने विकासशील देशों को खाद्य आयात पर टिके रहने हेतु ललचाया। परंतु यह गरीब की थाली में पोषक भोजन परोस देने के लिए काफी नहीं है और इससे उन छोटे किसानों की वास्तविक आय अर्जन के अवसरों की हानि की क्षतिपूर्ति भी नहीं हो सकती, जिनके कि अपने स्थानीय बाजार में आपूर्ति के अवसर समाप्त हो जाते हैं। क्रमबद्ध तरीके से अपनी कृषि सब्सिडी में कटौती कर विकसित देश विकासशील देशों के छोटे किसानों को अपनी आजीविका एवं स्थानीय समुदायों को भोजन उपलब्ध करवाने में सहायता कर सकते हैं।

अमीरों की विलासिता या गरीबों का जीवित रहना

जब इस मॉडल को सफल होने का मौका दिया जाएगा तभी विकासशील देशों को मौका मिलेगा और वे अपने छोटे खेतों को महाकाय निर्यात केंद्रित उत्पाद इकाइयों को बेच पाने का विकल्प ढूंढ पायेंगे। इसके बाद की उम्मीद की जा सकती है कि वैश्विक मूल्य इतने दयावान हो जायेंगे कि लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अनाज खरीद पायेंगे। सन् 2008 के खाद्य संकट के छः वर्ष बाद ''कृषि में पुनर्निवेश'' हुआ तो है लेकिन इसमें उत्पादन बढ़ाने के ढांचे के अलावा किसी और बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर और दक्षिण में सुधार के बिना और नये मानदंड निर्धारण के बगैर वैश्विक खाद्य प्रणाली ''नीलामी घर'' बनी रहेगी। जहां पर अमीर विश्व विलासिता का स्वाद, गरीबों की प्राथमिक आवश्यकताओं से लगातार प्रतिस्पर्द्धा करता रहेगा और जीतता भी रहेगा। *(सप्रेस)*

सूचना

आप सभी सुहृद पाठकों, ग्राहकों, लेखकों व शुभ-चिन्तकों से अनुरोध है कि अपने समसामयिक महत्त्वपूर्ण

आलेख

व क्षेत्रीय कार्यक्रमों की

रपट

पत्रिका के लिए जरूर भेजें। आप हमें अपने विज्ञापन भेजकर भी सहयोग कर सकते हैं। आपके सहयोग की सादर अपेक्षा है।

× × ×

आपकी सुविधा के लिए हमारी वेबसाइट

www.sssprakashan.com

पर 'सर्वोदय जगत' का प्रत्येक अंक उपलब्ध है। –सं.

अध्यात्म-सौरभ

गहरी नींद के सपनों में बनता देश

❑ राजेन्द्र माथुर

> ''जो लोग यह मानते हैं कि गद्य और तर्क के रास्ते राष्ट्रीयता सिखायी जा सकती है और मिथक का बहिष्कार संभव है, वे शायद यह भी मानते हैं कि बच्चों को राक्षस और परियों की कहानियां नहीं सुनायी जानी चाहिए, बल्कि उन्हें वह वयस्क समझदारी देनी चाहिए जो दूरदर्शन के सीरियल सबको दे रहे हैं।''

यूरोप के कई देश आज भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, लेकिन ईसा मसीह के स्वर्गारोहण की कथा के साथ-साथ प्रोमीथियस की वह कथा भी उनके सांस्कृतिक-विश्व का अंग बन चुकी है, जिसमें प्रोमीथियस अग्नि चुराकर लाता है और जीवनभर दुख झेलता है। बहुईश्वरवादी ग्रीस की कथाएं एकेश्वरवादी यूरोप की जातीय स्मृतियों में रच बस गयी है। ऐसा ही इंडोनेशिया में भी हुआ है, जहां रामायण की जीवित लोक परम्पराएं हैं और साथ ही साथ इस्लाम भी है। राम का परित्याग करके भारत का काम चल सकता है, लेकिन एक संस्कृति-पुरुष के नाते, एक काव्य प्रतीक के नाते राम का परित्याग करके कैसे काम चल सकता है? एक नास्तिक, विदेशी समाजशास्त्री जितनी संवेदना राम के चरित्र को दे सकता है, यदि उतनी भी हम देंगे तो क्या राष्ट्र को तोड़ने के पाप के भागी बनेंगे?

लोक से जुड़े हुए एक नेता राममनोहर लोहिया थे। उन्होंने रामायण मेलों का आयोजन क्यों किया और भारत के पुराण पुरुषों पर किताबें क्यों लिखीं?

जो लोग यह मानते हैं कि गद्य और तर्क के रास्ते राष्ट्रीयता सिखायी जा सकती है और मिथक का बहिष्कार संभव है, वे शायद यह भी मानते हैं कि बच्चों को राक्षस और परियों की कहानियां नहीं सुनायी जानी चाहिए, बल्कि उन्हें वह वयस्क समझदारी देनी चाहिए जो दूरदर्शन के सीरियल सबको दे रहे हैं। वे यह भी मानते होंगे कि कविता पाप है, कल्पना गुमराह करती है और मनुष्य का अवचेतन एक नरक है, जिससे बचकर ही हम अपने गद्य-स्वर्ग की ओर बढ़ सकते हैं। वे बेचारे नहीं जानते कि विज्ञान के चरम आविष्कारों में और मनुष्य के सबसे सृजनशील कर्मों में कल्पना का, अवचेतन का, आधी रात के सपनों का अतार्किकता के महासागर में गहरे डूबकर लोटने का कितना बड़ा हाथ रहा है। राष्ट्र को छोड़िए, लेकिन अवचेतन को समाप्त करके कोई व्यक्ति तब तक होश, समझदारी और पहचान नहीं पा सकता।

अतः भारत को यदि एक देश बनना है, तो यह जरूरी है कि हम सब एक ही अवचेतन विश्व के नागरिक बनें और देर रात जो सपने हम देखें, वे कमोवेश समान हों। जब तक सिंहासन के सवाल नहीं थे, तब तक यह समरूपता जरूरी रही होगी। भारत के विविध पंथों के लोग जब भक्त, कवि, पीर, वैज्ञानिक, मूर्तिकार या शिल्पी बनते होंगे, तब वे क्या एक ही अवचेतन महासागर के विविध जलों से प्रेरणा नहीं पाते होंगे? भारत में कविता लिखते समय क्या कबीर, खुसरो या रहीम भारत के कविता विश्व के आनंद से कटना चाह सकते थे? केरल में जो लोग हजार साल से ईसाई हैं, वे क्या उससे कटे हैं? उससे जुड़कर क्या वे कुछ घटिया ईसाई हो गये हैं? फिलिपीन के रोमन कैथलिक यदि फिलिपीन की स्थानीयता से जुड़े हैं और जापान के बौद्धों ने यदि गौतम बुद्ध का जापानीकरण कर दिया है, तो क्या वे कम ईसाई या कम बौद्ध हो जाते हैं?

जापान या फिलिपीन या इंडोनेशिया के उदाहरणों से एक और बात सामने आती है। यह जरूरी नहीं है कि देर रात के गहरे सपने स्वदेशी ही हों। वे मूलतः विदेशी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीयता के जन्म और विकास में सहायक हो सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी नहीं कि भारत के अवचेतन विश्व में सिर्फ रामायण और महाभारत ही हों। करबला और हुसैन भी हमारे मिथक विश्व के अंग हो सकते हैं और हिन्दुओं को भी उनके सपने आ सकते हैं। जब सिंहासन के प्रश्न नहीं थे, तब ईद और ताजिए क्या हिन्दू भागीदारी के त्योहार भी नहीं बनते जा रहे थे? आजकल की तरह नेताओं और अग्रणी नागरिकों की दिखाऊ फोटो खिंचाने वाली भागीदारी नहीं, बल्कि रेवड़ी वालों और कारीगरों की ईमानदार भागीदारी। भारत की हिन्दू रियासतों में जब सरकारी ताजिए बनाए और निकाले जाते थे, तब कोई राजा धर्मनिरपेक्षता या सर्वधर्म समभाव का नाम नहीं लेता था और न शायद तुष्टीकरण का कोई गणित उसके दिमाग में होता था। ताजिए निकालें और ईद मने, यह तब साँस लेने की तरह सहज बात थी और किसी को डर नहीं होता था कि ताजिया यदि किसी पीपल की फुनगी से टकरा गया, तो दंगे न हो जाएं। क्या उस सहजता

की ओर लौटना अब संभव नहीं है? क्या सारे ताजिए ठंडे करके, सारी मूर्तियों को तोड़कर और सारे सलीबों को जलाकर ही हिन्दुस्तान बन सकता है? ऊपरी तौर पर सोवियत रूस ने ऐसा किया, लेकिन क्या रूस आज अपने अतीत से कटा हुआ देश है? क्या वह अपने मिथक-नायकों से प्रेरणा नहीं पाता? धर्म का विनाश सम्भव है, लेकिन मनुष्य जाति की पुराण-चेतना का विनाश आज तक सम्भव नहीं हुआ।

दरअसल जिसे हिन्दू धर्म कहते हैं, वह इस लेख में वर्णित अर्थों में धर्म है ही नहीं। वह मिथक-संचय की भारतीय प्रक्रिया का नाम है। इस संचय प्रक्रिया को त्यागकर कोई देश नहीं बन सका, तो हिन्दुस्तान कैसे बनेगा, जिसकी निरंतरता तीन हजार साल से टूटी नहीं है? आशंका इस बात की है कि सिंहासन के झगड़ों के कारण और आसपास के दबावों के कारण कहीं यह संचय प्रक्रिया समाप्त न हो जाये और हिन्दुत्व सचमुच एक धर्म न बन जाये। आज हिन्दुत्व पर भारी दबाव है कि वह संकीर्ण, एकांकी और असहिष्णु बने। इन दबावों का जो जवाब हम अगले दस-बीस साल में देंगे, वहीं हिन्दुस्तान की किस्मत का फैसला सैकड़ों सालों के लिए कर देगा।

लेकिन यह उन धर्मों की भी जिम्मेदारी है, जो इस लेख के अर्थों में धर्म हैं कि वे भारत की इस संचय प्रक्रिया को नष्ट न होने दें। यदि वह नष्ट हो गयी तो न कोई धर्म शेष रहेगा, न यह प्रक्रिया। तब यह हिन्दुस्तान भी शेष नहीं रहेगा, जिसे सिंहासन के झगड़ों के अलावा हम तीन हजार साल से जानते रहे हैं। भारत की निरंतरता को जो खतरा इस माने में 1947 के बाद पैदा हुआ है, वह पहले सचमुच कभी नहीं हुआ, क्योंकि अब तो यह भी निश्चित नहीं है कि बीसियों राजनीतिक बंटवारों के बाद भी हिन्दुस्तान ज्यों का त्यों बना रहेगा, जैसे कि वह पहले बना रहता था। *(सप्रेस)*

आधी दुनिया

क्या स्त्री पुरुष के समान नहीं हो सकती?

❑ दादा धर्माधिकारी

हर पुरुष को आप कहेंगे ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है और हर स्त्री को कहेंगे कि मातृत्व श्रेष्ठ है। अर्थ तो वही हुआ कि हर स्त्री को विवाह करना चाहिए और किसी पुरुष को विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए गांधी की बात उस पुराने ब्रह्मचर्य की बात नहीं है। इसका अभिप्राय है कि स्त्री-पुरुष साथ रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, नितान्त विश्वास के साथ रहेंगे लेकिन निर्भयतापूर्वक रहेंगे।

आज स्त्री पुरुष के समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्या वह पुरुष के समान नहीं हो सकती? पितृत्व का जो स्थान पुरुष के भावनात्मक जीवन में है, वही स्त्री के भावनात्मक जीवन में मातृत्व का स्थान हो तो स्त्री पुरुष के समकक्ष आ सकती है। विनोबा पिता नहीं बना, उसका जीवन असफल नहीं है। जो स्त्री माता नहीं बनी, उसका भी जीवन असफल नहीं है, अपूर्ण भी नहीं है। यह एक नया मूल्य, जिसे मैं सामाजिक मूल्य कहता हूं, स्वीकार करना होगा। ब्रह्मचर्य का पुराना मूल्य पुरुष को सिखाता था कि वह स्त्री से दूर रहे। स्त्री को तो यह सिखा ही नहीं सकता था क्योंकि उसे मातृत्व की आकांक्षा थी। डिजरायली था न, वह बड़े मजे का आदमी था। उससे पूछा गया कि आप की शादी के बारे में क्या राय है? उसने कहा, सारी स्त्रियों को शादी करनी चाहिए और किसी पुरुष को शादी नहीं करनी चाहिए। अब ये बातें सुनने वालों को अटपटी मालूम होती हैं! लेकिन क्यों? हर पुरुष को आप कहेंगे ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है और हर स्त्री को कहेंगे कि मातृत्व श्रेष्ठ है। अर्थ तो वही हुआ कि हर स्त्री को विवाह करना चाहिए और किसी पुरुष को विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए गांधी की बात उस पुराने ब्रह्मचर्य की बात नहीं है। इसका अभिप्राय है कि स्त्री-पुरुष साथ रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, नितान्त विश्वास के साथ रहेंगे लेकिन निर्भयतापूर्वक रहेंगे।

स्त्री-स्त्री की ही मित्रता नहीं, स्त्री पुरुष की भी मित्रता तथा स्त्री और पुरुष का ऐसा संबंध, जहां पर यौन संबंध नहीं आता, स्थापित हो सकता है क्या? क्या स्त्री-पुरुष का संबंध प्रेम का संबंध हो सकता है? कौटुम्बिक और सामाजिक नागरिक के नाते इसके कुछ संकेत आपके सामने रख रहा हूं।

एक संकेत है हमारे यहां '**सीताराम**'। सीताराम संकेत का अर्थ है कि स्त्री और पुरुष का जो संबंध है, वह सबसे उत्कृष्ट है! सबसे निकट संबंध पति-पत्नी का ही संबंध है। स्त्री

और पुरुष पति पत्नी के नाते ही अत्यन्त निरापद भाव से एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं।

दूसरा संकेत है **'राधा कृष्ण'**। कृष्ण की किसी विवाहित पत्नी का नाम उसके साथ नहीं लिया जाता। महाराष्ट्र में सिर्फ विट्ठल भाई अवतार हैं। लेकिन जहां-जहां मैं गया राधेश्याम, राधेश्याम राधाकृष्ण, राधाकृष्ण ही है। कहीं सत्यभामा कृष्ण नहीं, रूक्मिणी कृष्ण नहीं। तो प्रियतम और प्रियतमा, लभर और विलभर का संबंध विवाहिता संबंध से भी आगे का संबंध है, जहां स्त्री अपना सर्वस्व दे देती है।

तीसरा संकेत है, **'द्रौपदी-कृष्ण'** का। यहां यौन संबंध नहीं है। प्रेमिका और प्रियतम भी नहीं है। पति पत्नी भी नहीं है। यौन निरपेक्ष संबंध है फिर भी पवित्र है, उत्कट है, मुक्त है। यह संबंध समाज में कब स्थापित हो सकता है? जब कुछ स्त्रियां ऐसी निकलेंगी। कहने की आवश्यकता नहीं कि सभी स्त्रियां ऐसी हो ही नहीं सकतीं। कुछ स्त्रियां ऐसी निकलें, जिनमें बुद्धि और हृदय की शक्ति पुरुषों से अधिक हो। जहां शारीरिक शक्ति कम होती है, वहां शारीरिक शक्ति के अभाव की पूर्ति के लिए उससे श्रेष्ठ किसी शक्ति की आवश्यकता होती है जो गांधी लेकर आया, इसलिए अंग्रेजों की शस्त्र-शक्ति उसके सामने ठहर नहीं सकी। स्त्रियों में जहां शारीरिक क्षमता कम है, वहां उसकी पूर्ति के लिए किसी दूसरी शक्ति का विकास करना पड़ेगा जिसके सामने शारीरिक शक्ति ठहर नहीं सकेगी। इसे आप नैतिक शक्ति कह लीजिए, चरित्र की शक्ति कह लीजिए। पुरानी नैतिक शक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। यह नयी मानवीय शक्ति है, जिसका विकास स्त्री को करना होगा। यह विकास होगा, तभी उसे समस्या में से निकलने का रास्ता मिल सकता है, अन्यथा समस्याएं ज्यों की त्यों रह जायेंगी।

एक दूसरे के जीवन में प्रवेश हो दखल नहीं

स्त्री जीवन की समस्याओं के उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं। ये उत्तर किसी के पास हैं नहीं। जीवन की समस्या की यह विशेषता होती है कि उसका बना-बनाया उत्तर किसी के पास नहीं होता। जो बना बनाया उत्तर देता है उसका उत्तर अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है। समस्याओं के उत्तर देने की कोशिश धर्मग्रंथों ने की। इसलिए सारे धर्मग्रंथ अपने आप में प्रश्न बन गये हैं। मनु की स्मृति, कुरान, बाइबिल सबके सब धर्म ग्रंथ अपने में एक प्रश्नचिह्न बनकर खड़े हैं। जीवन की समस्याओं के ऐसे उत्तर नहीं हो सकते। ऐसे उत्तर कहीं से लेने भी नहीं चाहिए। इस अर्थ में मेरा निवेदन है कि ग्रंथ-शास्त्र, पंडित-पुरोहित, गुरु इन सबसे मुक्त होकर समस्या का विचार करना चाहिए।

जब तक जीवन की समस्या की तरफ देखने की हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है, तब तक उसे देख नहीं सकेंगे। शुद्ध बुद्धि से मतलब हम किसी के चश्मे में से समस्या को नहीं देखते, नहीं देखना चाहते। हमारे सामने केवल एक ही चीज है और उसके संदर्भ में हम सब चीजों का विचार करेंगे। मनुष्य एक-दूसरे के साथ स्वतंत्रता और पवित्रता से जी सके। एक-दूसरे के साथ जीना ही जीना है, स्वतंत्रता से जीना ही जीना है। लेकिन स्वतंत्रता से जीने का मतलब अलग जीना नहीं है। स्वतंत्रता से कब जीया जा सकता है? जब मेरे जीवन में दूसरे का दखल न हो और दूसरे के जीवन में मेरा दखल न हो। एक-दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप न हो, लेकिन एक-दूसरे के जीवन में प्रवेश हो। हस्तक्षेप अलग चीज है और प्रवेश अलग चीज। जीवन में सहभागित्व होना चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए, दस्तनदाजी नहीं। तो क्या इस भूमिका पर स्त्री आ सकती है, बस इतना ही विचार है और कोई विचार हमारे सामने नहीं है। इसी विचार में से सारे प्रश्न और समस्याएं पैदा हुई हैं।

क्रांति की आकांक्षा

पुरुष-पुरुष इस भूमिका पर जा सकते हैं। यह विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। दुनिया के सांस्कृतिक विकास ने भी यही माना है, लेकिन संस्कृतियों ने और पुराने धर्मों ने इसको नहीं माना। विज्ञान के बाद मनुष्यों में जो विचार आये, कुछ विज्ञान के साथ आये, कुछ विज्ञान से पहले आये, उन्होंने मनुष्य समाज में एक संकल्प प्रकट कर दिया, व्यक्त कर दिया। संकल्प यह है कि मनुष्य मनुष्य के साथ बराबरी के नाते जी सकता है, जीना चाहिए। एक संकल्प है—किसी ने इसे समान अवसर कहा, किसी ने समानता कहा है। इस सबको छोड़ दीजिए। हर मनुष्य एक-दूसरे के साथ बराबरी के नाते जी सकता है, ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, पैदा की जानी चाहिए। इसे क्रांति की आकांक्षा कहते हैं। दूसरी आकांक्षा यह है कि अदना से अदना, छोटा से छोटा आदमी भी अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। उसके जीवन में, उसके व्यक्तित्व में जो संभावनाएं छिपी हुई हैं वे सारी की सारी संभावनाएं पूर्ण हो सकती हैं और इसकी समाज में व्यवस्था होनी चाहिए। ये दो चीजें हैं। मैं अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास कर सकूं; और दूसरे के साथ बराबरी के नाते जी सकूं। अकेले में यह हो नहीं सकता। अकेले में जीवन नहीं है; इसे सामाजिकता कहते हैं। क्या इसके लिए कोई जगह हो सकती है, यह सवाल मनुष्य के सामने आया। अब इस सवाल को हमें केवल एक संदर्भ में, एक विषय लेकर सोचना है—स्त्री और पुरुष।

—स्त्री और स्त्री के एक दूसरे के साथ बराबरी के नाते जी सकती है।

—पुरुष और पुरुष एक दूसरे के साथ बराबरी के नाते जी सकता है।

—स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के साथ बराबरी के नाते जी सकते हैं; लेकिन यह तभी संभव है, जब स्त्री को पुरुष का भय न हो और पुरुष को स्त्री का लालच न हो। ❑

('क्रांति की प्रक्रिया में नारी की भूमिका' से)

सामयिक

फिलीस्तीन : आग का गोला रोशनी नहीं होती

❑ चिन्मय मिश्र

'आवश्यकता क्रूर और कठोर प्रतिक्रिया की है। हमें समय, स्थान और हताहतों के संबंध में यथार्थता बरतनी होगी। यदि हम परिवार को जानते हैं जिसमें परिवार के बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, तो हमें निर्दयता से हमला करना होगा। अन्यथा यह प्रतिक्रिया अप्रभावशाली हो जायेगी। कार्यवाही वाले स्थान पर हमें अपराधी और निर्दोष के मध्य अंतर करने की आवश्यकता नहीं है।'

–डेविड बेन गुरियन

इजराइल के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री
1 जनवरी, 1948

इजरायल द्वारा गाजापट्टी पर किये जा रहे हमले का अब कई हफ्ते हो रहे हैं। संघर्ष में अब तक करीब 700 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। संघर्ष की शुरुआत 12 जून को तीन इजराइली किशोरों के अपहरण से हुई थी, जिनके शव बाद में हमास द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में मिले। इस दौरान एक फिलिस्तीनी बच्चे को भी अगवा किया गया और बाद में उसका जला हुआ शव बरामद हुआ था। इस बीच सुलह सफाई के काफी प्रयत्न भी हुए। मारे गये तीन इजरायली किशोरों में से एक नेफ्ताली की मां राशेल फ्रेकेल संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद् की एक बैठक में भाग लेने स्विट्जरलैंड भी गयी थी। वहां उन्होंने कहा कि 'नेफ्ताली एक अच्छा लड़का था जिसे गिटार बजाना और फुटबॉल खेलना पसंद था।' इस पर इजराइल के एक स्तंभकार गिडओन लेवी ने लिखा है 'मोहम्मद (मारा गया फिलीस्तीनी लड़का) भी एक अच्छा लड़का था जो विद्यालय से छुट्टी के दौरान अपना घर बनाने में अपने पिता की मदद करता था और परिवार के लिए मिठाई भी बेचता था। राशेल, नेफ्ताली को गले लगाना चाहती हैं? मोहम्मद के दुखी पिता जेहाद भी अपने बेटे को गले लगाना चाहते हैं। उन्हें कोई जेनेवा नहीं लाया। वे अपने उस आधे-अधूरे टूटे-फूटे मकान में ही शोक मना रहे हैं जो सम्भवतः अब कभी पूरा नहीं होगा।'

किसी भी युद्ध या आपसी संघर्ष से यूं तो पूरा समुदाय ही प्रभावित होता है लेकिन फिलीस्तीन की स्थिति कुछ अलग है। यहां की आधे से ज्यादा आबादी 21 वर्ष से कम के युवाओं की है और इसमें भी बच्चे बहुतायत में हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या यह संघर्ष महज इजरायली किशोरों की हत्या का परिणाम है? निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है। गायब हुए और बाद में मार डाले गये तीनों किशोरों की हत्या के लिए इजरायल ने 'हमास' को दोषी ठहराया। वहीं दूसरी ओर हमास ने इससे इनकार किया। सच्चाई जानने का बहुत प्रयास भी नहीं किया गया। इजराइल के अर्थमंत्री की यह टिप्पणी कि 'हमास की सदस्यता को नरक में प्रवेश का टिकट बना दो' वहां की सरकार की मानसिकता को एकदम स्पष्ट कर देती है। दूसरी ओर इजरायल के अंदर ही एक बड़ा वर्ग अब अपनी सरकारों की चरम दक्षिणपंथी नीतियों की खिलाफत कर रहा है और निरंतर युद्ध के 'मूड' में रहने का विरोध कर रहा है।

गाजापट्टी आज आग का गोला बन गयी है। हमास को दोषी ठहराकर और अत्यधिक बल प्रयोग क्या महज बदले की कार्यवाही है? अमेरिका अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है कि हमास के निर्माण में इजराइल का भी हाथ है। यासेर अराफात और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन का उत्थान व पतन, इसके बाद फतह का सत्तासीन होना और अब हमास का उभरना, महज संयोग नहीं है। यदि हम फिलीस्तीन की वर्तमान भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति पर गौर करें तो पता चलता है कि इस छोटे से राष्ट्र को दो हिस्से में बाँट-सा दिया गया है, एक हिस्सा पश्चिमी तट कहलाता है जहां पर फतह का शासन है और दूसरा हिस्सा गाजापट्टी का है जहां पर हमास का राज है। इन दोनों के बीच लम्बे समय से समझौते की चर्चा चल रही थी। अंततः 23 अप्रैल, 2014 को दोनों पक्षों ने साझा सरकार बनाने की घोषणा कर दी। बस यहीं से इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की त्योरियां चढ़ने लगीं। अमेरिका और यूरोप के देशों ने उन्हें इंतजार करने और सचेत रहने की सलाह दी और उन्होंने धैर्यपूर्वक इस घटना का इंतजार किया और युद्ध छेड़ दिया।

इजराइल के अमेरिका सहित अन्य मित्र राष्ट्र फिलीस्तीन में एकता की किसी भी संभावना को समाप्त कर देना चाहते थे। उनकी सोच थी फिलीस्तीन के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास को पूरी सत्ता सौंपकर वहां पर एक कठपुतली सरकार बना दी जाये जिसकी डोर पश्चिमी विश्व के हाथ में हो। इसीलिए युद्ध को चरम पर पहुंचाने के बाद मिस्र की नयी सरकार के माध्यम से युद्ध

विराम का जो प्रस्ताव तैयार करवाया गया, उसमें यह प्रावधान रखा गया कि हमास को अपने हथियार सौंप देने होंगे। भारत ने भी इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया। जबकि प्रसिद्ध स्तंभकार मिक-2 ने साफ लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार कब्जे वाले क्षेत्रों में आये व्यक्तियों की तरह हमास को भी हथियारबंद होने का अधिकार है। वहीं भारत सरकार का कहना है कि दोनों ही पक्ष हमारे मित्र हैं। तो ऐसी दोस्ती का क्या अर्थ है, जिसमें सही या गलत दोस्त को इंगित न किया जा सके? यह तो महज स्वार्थ सिद्धि ही कहलायेगा। क्या विश्व को विनाश से बचाने में किसी भी प्रकार की भूमिका निभाने में अब भारत असमर्थ हो गया है?

फिलीस्तीनी कवि इब्राहिम नसरउल्लाह की पंक्तियां हैं :

जी हां! यह मकान एक कब्र है
जिसमें एक दरवाजा और एक रोशनदान है
यह शयन कक्ष/आधा कफन है
और यह बिस्तर/आधा ताबूत

कई दशकों से फिलीस्तीन की यही वास्तविकता है। इस बार स्थिति की नाजुकता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अमेरिका के साथी देश तुर्की ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा परिषद् के पांच स्थाई सदस्यों में से चार ईसाई हैं और वे गाजापट्टी में इजराइल के हमले का समर्थन कर रहे हैं। गौरतलब है कि मिस्र से युद्धविराम समझौते का मसौदा तैयार करवाने में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव बान की मून की असहायता पुनः उभरकर सामने आयी है। चीन और रूस की चुप्पी भी सहमा देने वाली है जबकि पिछले दिनों सीरिया और इराक को लेकर ये लोग अत्यन्त सक्रिय थे। ब्रिक्स को लेकर हम सबको ख्वाब दिखाये जा रहे हैं कि यह शक्ति का नया केन्द्र बनेगा। वहीं भारत जो कि सुरक्षा परिषद् का स्थाई सदस्य बनना चाहता है अब बजाए अपनी स्वतंत्र विचारधारा के, महज लॉबिंग पर निर्भर हो गया है। इस सबके बीच युद्धविराम के इस समझौते का अप्रत्यक्ष अर्थ है इजराइल के कब्जे को वैश्विक मान्यता प्रदान करना।

पुनः फिलीस्तीन लौटते हैं। फिलीस्तनी कवियत्री इब्तिसम बरकत लिखती हैं :

हमारा शहर किसी कैदखाने की कोठरी है
बच्चों के चेहरे
गुलदानों की जगह ले रहे हैं
खिड़की की चौखट पर
और हम इंतजार कर रहे हैं

क्या यहां बच्चे अपनी चौखट पर बम के गिरने का इंतजार कर रहे हैं? वैसे भी यह पूरा क्षेत्र दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल ही कहलाता है। यहां पर इजराइल की मनमानी बरबस नाजी युग की याद दिलाती है, जिसका सबसे बड़ा शिकार स्वयं यहूदी ही हुए थे। लेकिन बदली परिस्थितियों में वे अत्यन्त निन्दनीय भूमिका निभा रहे हैं। यूनिसेफ के अनुसार सन् 2000 से अब तक इजराइल द्वारा यहां तकरीबन 1400 बच्चों को मारा जा चुका है। इसमें से मात्र 40 कथित अवैध गतिविधियों में लिप्त पाये गये थे। यानी इजराइल हर तीसरे दिन 13 वर्ष से अधिक उम्र के एक बच्चे को मार रहा है। इतना ही नहीं यहां बच्चों को इतनी यातना दी जाती है कि 95 प्रतिशत बच्चे 'स्वीकारोक्ति' कर लेते हैं। गौरतलब है इस बार की बमबारी में घरों व दुकानों के अलावा विद्यालय, अस्पताल, शिशुघर, वृद्धाश्रम और खेल के मैदानों को भी निशाना बनाया गया है।

कमाल नासिर एक कवि होने के साथ फिलीस्तीन मुक्ति संगठन के प्रवक्ता भी थे। 13 अप्रैल, 1973 को इजराइली डेथ स्क्वाड ने लेबनान में उनकी हत्या कर दी थी। उनकी कविता की पंक्तियां हैं :

बताना मेरे बच्चे को
यदि वह मेरी कब्र पर आये
और मुझे याद करे/कि एक दिन मैं लौटूंगा
फलों को इकट्ठा करने के लिए।

लेकिन आज तो गाजापट्टी में पिता के कंधों पर बच्चों की लाशें हैं और क्या वह अपने बच्चे की कब्र पर दोबारा आने की हिम्मत जुटा पायेगा? कल्पना कीजिए उन सैकड़ों पिताओं का जो अपने बच्चों को दफनाकर आने के बाद उनकी मां की आंखों का सामना कैसे कर पायेंगे।

बहरहाल हम और हमारा देश तो सबसे दोस्ती निभाते रहेंगे। *(सप्रेस)*

दिनेशचन्द्र शुक्ल नहीं रहे

बिहार सर्वोदय मंडल की कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य तथा पटना महानगर सर्वोदय मंडल के संरक्षक दिनेशचन्द्र शुक्ल का 4 अगस्त, 2014 को पटना में निधन हो गया।

स्व. शुक्ल वातायन मीडिया एण्ड पब्लिकेशन प्रा. लि. तथा मासिक पत्रिका 'वातायन प्रभात' के संस्थापक व संरक्षक थे। श्री शुक्ल ने पटना में 18-19 मार्च, 2013 को आयोजित सर्व सेवा संघ अधिवेशन के अवसर पर 'वातायन प्रभात' का 'संपूर्ण क्रांति से सर्वोदय' नामक विशेषांक निःशुल्क प्रकाशित एवं वितरित कर अपना बहुमूल्य योगदान आयोजन में दिया था।

इस बीच सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष महादेव विद्रोही एवं प्रवक्ता भवानीशंकर कुसुम ने दिनेश शुक्ल के देहावसान पर गहरी संवेदना व्यक्त की है तथा श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिहार सर्वोदय मंडल की अध्यक्षा कल्पना अशोक, पटना महानगर सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष अशोक मोती ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए स्व. शुक्ल को सादा जीवन, उच्च विचार की प्रतिमूर्ति बताया है।

सर्व सेवा संघ के ट्रस्टी डॉ. रामजी सिंह एवं मंत्री विजय भाई ने शुक्लजी के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए इसे सर्वोदय आंदोलन की बड़ी क्षति बताया है।

पटना महानगर सर्वोदय मंडल के लोकसेवकों एवं सर्वोदय मित्रों की एक शोकसभा उपाध्यक्ष शिवशंकर ठाकुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें मंत्री डॉ. अमजद अली खान सहित भारी संख्या में उपस्थित लोकसेवकों एवं सर्वोदय मित्रों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 'सर्वोदय जगत' और संपूर्ण सर्वोदय परिवार की ओर से श्री शुक्लजी को हार्दिक श्रद्धांजलि। **–स.ज. संवाददाता**

जीवन का विज्ञान है, आयुर्वेद

हे प्राचीन भारत भूमि! हे मानव जाति का पालन करने वाली। हे पूजनीया! हे पोषण दात्री! तुझे नमस्कार है। शताब्दियों से लगातार चलने वाले पाशविक अत्याचार तुझे आज तक नष्ट नहीं कर सके। तेरा स्वागत है। हे श्रद्धा, प्रेम, कला और विज्ञान की जन्मदात्री! तुझे नमस्कार है।

—एम. लुई जेकोलियट

वह कौन-सा पुण्य दिवस था, जब भारतीय संस्कृति की पहली सुबह हुई, यह आज तक कोई नहीं बता पाया। इस महान् संस्कृति के प्रवर्तक वे महापुरुष हैं, जिन्होंने ईश्वर और प्रकृति के रहस्य को आदि से अनन्त तक अनुभव कर लिया था, जो जीवत्व से ब्रह्मत्व को प्राप्त कर चुके थे। इसीलिए इस संस्कृति में जीव को परमानन्द में लय करने के गुण हैं।

किसी भी विद्वान से यदि यह पूछा जाय कि सबसे पुरानी चिकित्सा-पद्धति कौन-सी है, तब वह बिना देरी किए तत्काल यही जवाब देगा कि निश्चित रूप से आयुर्वेद। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कठिन है कि आयुर्वेद का जन्म कब हुआ?

शास्त्रों में लिखा है कि किसी समय आयुर्वेद का समस्त सार लेकर ब्रह्माजी ने एक ग्रंथ रचा, जिसका नाम था 'ब्रह्मसंहिता'। उस ग्रंथ में एक लाख श्लोक थे, जिनमें सारा आयुर्वेद समाया हुआ था, लेकिन वह अब लुप्त है। आचार्य सुश्रुत ने इस बारे में लिखा—ब्रह्माजी ने अथर्ववेद के उपांग स्वरूप आयुर्वेद एक लाख श्लोकों में ग्रंथित किया था, जिसमें एक हजार अध्याय थे। ब्रह्मसंहिता रचने के बाद मानव उपकार के लिए उन्होंने दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद पढ़ाया। दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद को प्रयोगात्मक रूप दिया। दक्ष प्रजापति ने दोनों अश्वनी कुमारों को आयुर्वेद पढ़ाया। त्वष्टा और पुत्री संज्ञा से जुड़वा संतान दस्र और नासत्य हुईं। इन्हीं का संयुक्त नाम अश्वनी कुमार था। उन दोनों भाइयों ने आयुर्वेद से बहुत यश पाया, उनकी अदभुत चिकित्साओं से इन्द्रदेव उन पर बेहद प्रसन्न हुए और उनसे आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। देवलोक में देवताओं को ये दोनों भाई आयुर्वेद से लाभान्वित करने लगे।

च्यवन ऋषि को पुनर्यौवन देना, दक्ष प्रजापति के सिर को पुनः जोड़ देना, दाँतों के गिर जाने पर पुनः दाँत उगा देना, राजयक्ष्मा को मिटा देना, टाँग कटने पर लोहे की नकली टाँग जोड़ देना जैसे चकित कर देने वाले कार्य इन्होंने किये।

शास्त्रों में लिखा है कि देवलोक में जाकर इन्द्र से ऋषि भरद्वाज ने आयुर्वेद की शिक्षा ली। इसके बाद आयुर्वेद के इतिहास में भगवान धन्वंतरीजी का नाम आता है। ये ऋषि भरद्वाज के शिष्य थे।

अश्वनी कुमारों से आयुर्वेद की शिक्षा लेने के बाद महर्षि आत्रेय को इन्द्र ने आयुर्वेद सिखाया। महर्षि आत्रेय ने आयुर्वेद को और व्यापक बनाने की मंशा से अग्निवेश, भेड़, जातुकर्ण, पराशर, क्षीर पाणि और हारीत को आयुर्वेद सिखाया। पारंगत होने के बाद इन ऋषियों ने अपने-अपने नाम से आयुर्वेद ग्रंथों की रचना की।

अब आया चरक का युग। चरक ने अग्निवेश, हारीत आदि ऋषियों के ग्रंथों का सार-मर्म लेकर तथा अपने अनुभवों को जोड़कर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है, 'चरक संहिता'।

'चरक संहिता' के बारे में आज भी यही कहा जाता है कि जिसने 'चरक संहिता नहीं पढ़ी वह वैद्य नहीं यमदूत है।' विदेशी विद्वान भी मानते हैं कि यदि दुनिया भर के चिकित्सक 'चरक' की बतायी विधियों से इलाज करें तो मनुष्य जाति का महान् उपकार हो जाये।

महात्मा विश्वामित्र के पुत्र 'सुश्रुत' का नाम 'चरक' के बाद आता है। इन्होंने काशी में रहकर काशिराज दिवोदासजी से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। दिवोदासजी के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान धन्वंतरी के अवतार थे। दिवोदासजी के उपदेशों को सुश्रुत बहुत ध्यान लगाकर सुनते थे, इसीलिए इनका नाम 'सुश्रुत' पड़ गया।

आज दुनिया भर में शल्य चिकित्सा का बोलबाला है। एक-से बढ़कर एक हैरतअंगेज कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं—हो रहे हैं। शल्य चिकित्सा ने चिकित्सा-क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि विश्व में अपनी उपयोगिता का डंका बजाने वाली इस शल्य चिकित्सा की शुरुआत अपने देश भारत से ही हुई थी। आचार्य सुश्रुत ने अपने रचे ग्रंथ 'सुश्रुत' में सर्जरी पर बहुत खूबी से जानकारियां दी हैं।

'वाग्भट' नाम के महान् आयुर्वेदाचार्य का नाम चरक और सुश्रुत के बाद आता है। आयुर्वेद में 'वाग्भट' का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। 'वाग्भट' महाभारतकालीन थे। कहा जाता है कि आप महाराज युधिष्ठिर के मुख्य चिकित्सक थे। आपने चरक और सुश्रुत का सहारा लेकर 'अष्टांग हृदय' नामक ग्रंथ की रचना की, इसे 'वाग्भट' के नाम से भी जाना जाता है।

आयुर्वेद जगत में 'वाग्भट' के बाद 'बंगसेन' नामक आयुर्वेदाचार्य को प्रसिद्धि मिली। कहा जाता है कि बंगाल में जन्मे बंगसेन का जन्म ईसा से चार-पांच सौ साल पहले हुआ था। इनकी रचना 'बंगसेन' की अपनी विशेषता है। सरल तथा आसानी से समझ में आने वाली शैली में लिखा 'बंगसेन' अत्यन्त उपयोगी सामग्री से भरा हुआ है।

('निरोग सुख' पुस्तिका से 'साभार')

गतिविधियां एवं समाचार

लोकसेवक व सर्वोदय-मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम :

उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल का तीन दिवसीय 27-28 एवं 29 जुलाई, 2014 को सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी में लोकसेवक व सर्वोदय-मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस शिविर का उद्घाटन सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष श्री महादेव विद्रोही ने किया। अतिथियों एवं प्रतिभागियों के परिचय के पश्चात् प्रारम्भिक सत्र में उन्होंने वर्तमान समय की चुनौतियों एवं समाधान तथा सर्वोदय विचार की प्रासंगिकता पर विस्तार से समझाया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पधारे लोकसेवकों एवं सर्वोदय-मित्रों ने भी समूह चर्चा के दौरान द्वितीय सत्र में परस्पर विचार बांटे, जिससे जीवनशैली पर बदलाव की आवश्यकता सभी ने महसूस की।

उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष डॉ. मधुसूदन ने साधना, योग, प्राणायाम, स्वाध्याय तथा मानव स्वास्थ्य पर गंभीरतापूर्वक प्रकाश डाला। सर्वोदय जगत पत्रिका के कार्यकारी संपादक अशोक मोती ने श्रमदान-सफाई के महत्त्व पर विस्तृत जानकारी दी तथा जीवन में इसकी उपयोगिता बतायी। ग्राम स्वराज्य विषय पर सर्व सेवा संघ के पूर्व श्री अमरनाथ भाई ने अपने प्रबोधन में विस्तार से ज्ञानवर्धन किया तथा देर न करते हुए इस दिशा में सार्थक पहल करने को कहा। जल-जंगल-जमीन के मुद्दे पर सर्व सेवा संघ प्रकाशन के संयोजक अशोक भारत ने महत्त्वपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया। स्त्री-शक्ति की अस्मिता के संकट को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर होकर कार्यक्रम निर्धारित करने का आह्वान उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल की मंत्री जागृति राही ने किया। उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के मंत्री एवं सर्व सेवा संघ परिसर, वाराणसी के संयोजक शिवविजय सिंह ने गांधी के सुझाए 18 रचनात्मक कार्यक्रमों में से अपनी रुचि के मुताबिक कोई एक कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया। यदि एक कार्यक्रम भी अच्छे से लागू कर पायें तो वही सफलता होगी। अन्तिम वक्ता के रूप में पधारे भाई रामधीरज ने सर्वोदय जमात में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने शहर, कस्बे एवं गांव में सर्वोदय मित्र बढ़ाने एवं युवतियों को भी आगे आने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाय, जिससे रासायनिक खादों का चलन रुके। जनपद बदायूं, चित्रकूट, हमीरपुर, देवरिया, गाजीपुर, इलाहाबाद, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी आदि जनपदों से पधारे लोकसेवकों एवं सर्वोदय-मित्रों के प्रति उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष डॉ. मधुसूदन ने आभार व्यक्त किया।

–शिवविजय सिंह

अखिल भारतीय नशाबंदी कार्यकर्ता सम्मेलन

23-24 सितंबर, 2014, वाराणसी में

नशों की बुराइयों को कौन नहीं जानता, शराब पापों, अपराधों और सभी बुराइयों की जननी है। समाज में मार-काट, लूट-खसोट, चोरी-डकैती, सड़क दुर्घटनाएं, महिलाओं की चेन और पर्स झपटना, उनके साथ छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी शर्मनाक घटनाओं में अधिकांशतः शराब सेवन करने वाले व्यक्तियों का हाथ रहता है। पूरे समाज में मादक द्रव्यों के व्यापार से जुड़े माफियाओं का आंतक है, तो घर के अंदर शराबी पति, बाप, भाई और बेटों के जुल्मों से ग्रस्त मां, बेटी, बहन और पत्नी, बच्चे बुरी तरह प्रभावित हैं। शराब व अन्य सभी मादक पदार्थों के सेवन से समाज का सर्वनाश हो रहा है और हमारी युवा पीढ़ी का जीवन बर्बाद हो रहा है।

यह विडम्बना ही है कि हमारी भारत सरकार और प्रांतीय सरकारें जो रामराज्य की बात करती हैं, वे शराब की अनैतिक आय के मोह में फँसी हैं। उनका यह कृत्य देश की जनता विशेषकर गरीब, युवा एवं महिला वर्ग की तबाही का कारण बना हुआ है। पूरे भारत में केवल गुजरात राज्य ही एकमात्र ऐसा है जहां आजादी के बाद से आजतक किसी भी सरकार को शराब की बिक्री से कोई आय नहीं हुई है, फिर भी विकास में आगे है। पूर्व में आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, राजस्थान और तमिलनाडु में महिलाओं के आंदोलनों से वहां किसी न किसी रूप में शराब बंदी रही थी। परंतु सरकारों ने फिर शराब चालू कर ली है। आज फिर आवश्यकता है कि देश की महिलाएं और छात्र-छात्राएं शराबबंदी के लिए आंदोलन कर देश को बचायें। यह सम्मेलन देश और समाज को इस बुराई के खिलाफ खड़े होने का आह्वान करता है और आशा करता है कि सब मिलकर इस बुराई को समाप्त कराने में अपना-अपना योगदान करेंगे।

सम्मेलन स्थल एवं तिथि

सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी में यह सम्मेलन 23 सितंबर को अपराह्न 2 बजे प्रारम्भ होगा और 24 सितंबर 2014 तक चलेगा।

कैसे पहुंचे

1. वाराणसी के लिए देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से सीधी ट्रेनें हैं।

2. वाराणसी एवं मुगलसराय जंक्शन से आने वाले प्रतिनिधि रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर मुगलसराय जानेवाली बसों या ऑटो से राजघाट (बसंत कॉलेज मोड़) पहुंच सकते हैं।

संपर्क

1. श्री शिवविजय सिंह, संयोजक, सर्व सेवा संघ परिसर, मो. 9415497204
2. श्री विजय भाई, मंत्री, सर्व सेवा संघ, मो. 9430622833
3. कृपया अपने पहुंचने की सूचना केन्द्रीय कार्यालय को देने का कष्ट करेंगे तो व्यवस्था करने में सुविधा होगी।

महादेव विद्रोही
अध्यक्ष
सर्व सेवा संघ

महावीर त्यागी
महामंत्री
अ.भा. नाशंदी परिषद

और अंततः

21 अगस्त : पुण्यतिथि

काका कालेलकर का पुण्य-स्मरण व नमन!

❑ अशोक मोती

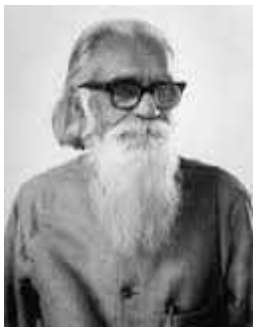

काका साहब कालेलकर के पुण्य-स्मरण में हमारा लाभ और लोभ दोनों है। लोभ है कि काका बहुआयामी प्रतिभा सम्पन्न ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे जिनसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जैसे शीर्षस्थ नेता, आंदोलनों व प्रति आंदोलनों के बारे में उनसे राय-मशविरा करते थे, स्वाभाविक है, कोई उन्हें जानने के लोभ का संवरण करे भी तो कैसे?

सच कहूं तो स्कूल-कॉलेज में खासकर शिक्षा में परिवर्तन जैसे विषय में गांधी से अधिक काकासाहब का नाम ही सुनता रहा। कॉलेज के दिनों में पूणे के फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम भी काकासाहब कालेलकर के कारण ही जान पाया था, जहां उन्होंने पढ़ाई की थी। और जिस कॉलेज में पढ़ने का शौक न जाने कितने युवा पालते रहते हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज तक की यात्रा ही काका के लिए कम कठिन नहीं थी। बाद के जीवन में तो न जाने कितने मोड़ आये।

उनका जन्म भी कम रोमांचकारी नहीं है। एक साधु के कहने पर ही उनका गुरु दत्तात्रेय के नाम पर उनका नाम दत्तात्रेय रखा गया था और यह दिवस था पहली दिसम्बर, 1885 जिन्हें लोग निश्चित ही 'दत्तू' के नाम से पुकारते थे। काफी बड़े होने तक वे स्वयं अपने हाथ से नहीं खाते, इसलिए घर के लोग उन्हें ऊँट भी कह देते। जिन्हें खाने के लिए अपने दांये और बायें हाथ कौन है और किससे खाएं, यह भी पता नहीं था, ऐसे व्यक्ति का देश में एक राष्ट्र-निर्माता के रूप में उभरकर आने के जीवन-इतिहास पढ़ने के लाभ को भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। काका को पढ़ने में किंचित् लोभ से अधिक तो लाभ है।

काका साहब के जीवन ने ही उनमें यह अनुभूति गहराई से डाल दी थी कि भगवान जो करता है वह हमारी भलाई के लिए ही करता है। लेकिन दत्तू ने बाद में शिव को गुसैल देवता के कारण, श्रीकृष्ण को व्यभिचारी मानने के कारण, गणपति को विद्या का देवता जिसकी अपनी पूजा स्कूल में की जाने के कारण, सूर्य का मंदिर कहीं न मिलने के कारण और देवी का स्त्री होने के कारण कभी उपास्य के तौर पर चुनने लायक नहीं समझा। अपने नाम वाले गुरु दत्तात्रेय की उपासना ही सही माना। गुरु गुलर के पेड़ के नीचे बैठते तो ये स्वयं भी बैठते, गुरु को सेम की सब्जी पसंद थी तो दत्तू भी सेम की सब्जी ही खाते। अंत में सबको छोड़ सिर्फ ॐ ॐ की ध्वनि निकालने के आदी हो गये। समुद्र मंथन की कथा पढ़कर पाया कि सभी देवता भारी लालची सिद्ध हुए थे—रत्न बटोरकर ले जाते, विष्णु का व्यवहार बड़ा बुरा लगा था कि उन्होंने रत्न के अतिरिक्त लक्ष्मी को भी हड़प लिया था। शिवजी ही एक मात्र देवता ऐसा निकले जिन्होंने हलाहल को दुनिया से दुख दूर करने के लिए कंठ में डालकर नीलकंठ कहलाये। शिवजी से ही प्रेरणा मिली कि मुझे भी इसी तरह जीवन में चलना चाहिए।

22 जून, 1897 को प्लेग निवारण समिति के दो बड़े अंग्रेज अफसरों रैण्ड और आयर्स्ट की पुणे में हत्याएं हुईं। लोकमान्य तिलक की ख्याति उन दिनों शिवाजी के आधुनिक अवतार की तरह थी जिन्हें गिरफ्तार कर जेल की सजा दे दी गयी थी। एक दिन लिंगायत सम्प्रदाय के दो साधु जहां दत्तु रहते थे, आकर घूमने लगे जिसे लोगों ने जासूस माना। दत्तू के नेतृत्व में उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ साधु को गली में घेर कर इतनी पिटायी की कि वे भाग ही गये। दत्तू ने अपने तीन भाइयों के साथ एक गुप्त मंडली की स्थापना भी कर ली जिन्हें शिवाजी की तरह गुप्त रूप से काम करना था। अंततः वे एक क्रांतिकारी दल में शामिल भी हो गये। देश के लिए मर मिटने के उनके संकल्प की पुष्टि जैसी स्थिति ने अपने ढंग से कर दी हो। काका ने अपने सामने अपने पिता को अपनी किसी गलती पर गिड़गिड़ाकर 'योर ऑनर अलोन कैन सेव मी नाऊ' बोलते देख और कलक्टर से दुत्कार पाते देख दत्तू का दिल बगावत के लिए खड़ा हो गया—'मैं इन गोरे का राज तोड़ डालूंगा।' बस जिन्दगी में और कुछ भी नहीं करूंगा, यही एक काम करता रहूंगा—के दृढ़ निश्चय ने अंततः दत्तू को काका कालेलकर बनने को प्रेरित कर ही दिया। गोखले ने फर्ग्यूसन के छात्रों को देश- सेवा के लिए समर्पित होने का आह्वान किया। लेकिन काका बनने पर उनके सामने गोखले के आदर्शों को और भी ठोस रूप से क्रियान्वित करने वाले गांधी उन्हें मिल गये थे। इमान-मात्र मेरा क्षेत्र है, यह उनका जीवन सूत्र था, पर इमान के लिए इमान में या जो इमान हमें स्वतंत्रता की ओर नहीं ले जाता उसमें उनकी कोई रुचि नहीं थी। गांधी के संपर्क में ऐसे विचारों का पोषण मिलना स्वाभाविक था।

सितंबर 1939 से अगस्त 1942 तक काका साहब मानो एक मसीहा की तरह बलिदान की अमोघता पर बोलते-लिखते रहे। महसूस करने लगे कि गांधी इस देश में एक अभिनव प्रयोग अहिंसा का करने जा रहे हैं। सरकार को सूचना देकर पुल उड़ाने की कार्रवाई और तोड़-फोड़ को अहिंसा के व्याकरण में बिठाए जाने की कोशिश की। तोड़फोड़ के समर्थन में दो-तीन लेख लिखते

ही गिरफ्तार कर लिये गये। जेल गये तो अहिंसा पर एक प्रबंध ही लिख डाले— 'अहिंसा का युग आ रहा है'। उन्हें एक जेल में रहने नहीं दिया गया। जिन छः जेलों में घुमाया उनमें 3 जेलों में नागपुर, बेलौर और सिवनी में वे विनोबा और किशोरलाल भाई के साथ ही रहे। गांधी के विचारों से उनका असाधारण परिचय था। 25 वर्षों से वैचारिक भूमिका पर काका और विनोबा, गांधी के साथ रहे। तीनों के बीच तीन वर्षों तक चर्चाएं— गांधी की जीवन-दृष्टि, अहिंसा, संस्कृति, धर्म समन्वय, अध्यात्म व विज्ञान का समन्वय, भाषा, साहित्य, लिपि, राष्ट्र-जीवन और मानव-जीवन से संबंधित कोई विषय उनसे अछूता नहीं रहा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसपर काका ने काफी गंभीरता से काम न किया हो। उम्र में विनोबा उनसे दस साल छोटे थे इसलिए काका का उनके लिए मन में आदर भी था और वात्सल्य भी।

काका साहब का विश्वास था कि यह दुनिया अनाथ नहीं है, इसका संचालन करने वाली एक शक्ति है। यह अनुभव जैसे उनके जीवन में एकाकार हो गया हो।

गांधी के बलिदान के बाद छः हफ्तों में यानी 1948 के मार्च मध्य में उनके जिम्मे गांधी के जीवन पर एक संग्रहालय बनाने का भार आया। काका साहब संगठक बनाये गये और उन्होंने बड़ी लगन से काम शुरू भी किया किन्तु इस उद्देश्य से कि गांधी को लोग भगवान बनाकर पूजने न लग जायें और उनके आदर्श को अपनाये ही नहीं। काका साहब कहते थे कि यदि गांधी को बचाना है तो एक म्युजियम खड़ा करो वरना लोग मंदिर खड़ा कर गांधी को जो सत्य का उपासक रहा उसकी असत्य कथा को फैलायेंगे जो गांधी-द्रोह होगा। राजघाट, दिल्ली में गांधी की समाधि के पास ही यह गांधी स्मारक संग्रहालय आज भी स्थापित है 'गांधी दर्शन'। संपूर्ण गांधी वाङ्मय प्रकाशन में उनका बड़ा योगदान है। 1953 में पिछड़े वर्गों की स्थिति पर अध्ययन हेतु गठित आयोग की अध्यक्षता कर और संपूर्ण स्त्री जाति को जिनमें उच्च वर्ग की पढ़ी-लिखी महिलाएं आ जाती हैं, उन्होंने पिछड़ी जातियों में समाविष्ट कर दिया था। पत्रकार, शिक्षक या मिशनरी काका साहब ने एक विशाल साहित्य की भी रचना की जो सिर्फ व सिर्फ वे ही लिख सकते थे।

अंततः काका साहब के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं यह मानता हूं कि उन्होंने गांधी को बचा लिया था, उन्होंने उन्हें भगवान नहीं बनने दिया।

ऐसे महान काका साहब को श्रद्धासुमन व कोटि-कोटि नमन! ❑

संपादक के नाम पत्र

... जिसे हम सभी गांधीजनों को पढ़ना चाहिए

'सर्वोदय जगत' का नया रूप निश्चित रूप से आकर्षक और लुभावना है। आवरण पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ सामग्री के प्रकाशन के ढंग में भी सकारात्मक बदलाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन विविधता की अभी भी गुंजाईश है। मात्र आदर्शवादी लेखन से पूर्व में पत्रिका कुछ बोझिल लगती थी। विषयों की विविधता एवं समकालिक/तात्कालिक विषयों को शामिल कर इसे और आकर्षक बनाया जा सकता है। चित्र देने से भी इसके कलेवर में निखार आया है।

लेकिन छपी प्रतियों की संख्या मात्र 1400 बहुत ही अखरने वाली है। कुछ वर्ष पूर्व इस अकिंचन ने एक साल में 200 ग्राहक बनाये थे। दूसरे वर्ष 120 ग्राहकों का शुल्क गांधी जयंती पर जैसलमेर पधारे सर्व सेवा संघ के तत्कालीन अध्यक्ष भाई अमरनाथ को सौंपा था। गत वर्ष खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद, जैसलमेर से जिले की 130 विद्यालयों में 'सर्वोदय जगत' भिजवाने का प्रस्ताव (संचालक मंडल का सदस्य होने के कारण) पारित कराकर राशि भिजवायी गयी थी। अंतर्राष्ट्रीय पाक सीमा पर स्थिति जैसलमेर (राजस्थान) में ऐसे प्रयास हो सकते हैं, तो कम से कम हिन्दी भाषी प्रांतों में इसका विशेष अभियान क्यों नहीं चलाया जा सकता? 'सर्वोदय समाज' के सम्मेलनों में जिन सर्वोदयियों की भीड़ उमड़ती है, क्या वे सब एक मेले के दर्शक मात्र हैं? या घूमने-फिरने का आनंद उठाने वाले हैं। सम्मेलन का एक-एक भागीदार अगर 10-10 ग्राहक भी बनाये तो यह संख्या हजारों में बैठती है। देश के हर जिले में कम से कम एक आजीवन सदस्य होना ही चाहिए। मैंने भी पांच आजीवन सदस्य बनाये थे।

यही हाल विज्ञापनों का है। मैं विगत लगभग 10 वर्षों से भी अधिक से 'सर्वोदय जगत' का ग्राहक (पाठक) हूं। कुछ अर्से पूर्व (प्रारम्भ में) मैंने प्रयत्नपूर्वक 5-6 विज्ञापन भिजवाये थे। मेरी जानकारी में उन विज्ञापनों के अलावा मैंने इस पत्रिका में शायद ही कोई अन्य विज्ञापन देखा हो। क्या हम सर्वोदयी इतने असहाय या जनता से कटे हुए हैं कि प्रति अंक कम से कम एक विज्ञापन भी नहीं जुटा सकते? खादी एवं गांधी विचार की रचनात्मक प्रवृत्तियों वाली संस्थाओं को चाहिए कि वे अनिवार्य रूप से अपना कर्तव्य समझ कर अपना विज्ञापन दें, तभी ऐसी पत्रिकाएं जिन्दा रह सकती हैं एवं विस्तार पा सकती हैं।

पूर्व में पत्रिका पक्षांत के भी एक माह पश्चात् मिलती थी, अब पक्षारम्भ के 7 दिनों में ही मिलने लगी है। एतदर्थ एवं नये रूप तथा कलेवर में परिवर्तन, संशोधन, संवर्द्धन के शुभ प्रयासों हेतु पुनः साधुवाद। मैं पत्रिका के उत्तरोत्तर विस्तारित होने की कामना करता हूं। **–किशनगिरि गोस्वामी**

× × ×

सेवाग्राम में सर्व सेवा संघ की 1-2 अगस्त, 2014 को आयोजित बैठक में 'सर्वोदय जगत' के और भी बेहतर प्रकाशन एवं प्रसार संख्या बढ़ाने पर विमर्श हुआ है। आप अपने विचारों से इसी तरह सदैव अवगत कराते रहें ताकि हम पत्रिका को और भी बेहतर बना पायें। आपके सुझावों का स्वागत है। **–का. सं.**

हाँफ रही है पूंजी

❑ सुशील कुमार

बहुत तेजी से भागती है पूंजी
मानो वक्त से
आगे निकल जाना हो इसे
मानो अपनी मुट्ठी में दबोच लेना हो
समूचा ब्रह्माण्ड समूची धरती
खेत, नदियां और पहाड़
बच्चों की किलकारियां
मजदूरों का पसीना,
किसानों का श्रम,
मेहनतकशों के हकूक,
आज़ादाना नारे
और वह सब कुछ
जो उसकी रफ्तार के आगे आता हो
वह बढ़ाना चाहती है
अपनी रफ्तार
प्रतिपल
लेकिन बहुत जल्दी
हाँफने लगती है पूंजी
और जब पूंजी हाँफने लगती है
तब खेतों में अनाज की जगह
बंदूकें उगाई जाती हैं
भूख के जवाब में
हथियार पेश किये जाते हैं
परमाणु, रसायन व जैविक
पूंजी पैदा करती है
दुनिया के कोने-कोने में
रोज नये पाकिस्तान
उत्तर-दक्षिण कोरिया
चीन, जापान
इजराइल, फिलिस्तीन
फिर हँसती है
दोनों हाथ
जंघों पर ठोकर
सोवियत संघ के अंजाम पर
अफगानिस्तान पर, ईराक पर,
मिस्र पर
अपनी हँसी खुद दबाकर
बगलें झाँकती है पूंजी
वेनुजुवेला और क्यूबा के
सवाल पर
दम फूल रहा है प्रतिपल
हाँफ रही है पूंजी
और खेतों में अनाज की जगह
उग रही हैं बंदूकें
पूंजी आत्मघाती हो रही
है दिनोंदिन। ❑

बच्चे यह पूछते हैं ...फिलिस्तीन कहां है?

❑ नरेन्द्र कुमार मौर्य

जो खून बहाये हैं वो जमीन कहां है
बच्चे ये पूछते हैं फिलिस्तीन कहां है

कौन है जो बम ही गिराए हैं रात-दिन
दुनिया को है मालूम वो जमीन कहां है
कत्ल करके वो पाक-साफ ही रहा
कातिल भी अमां देख बेहतरीन कहां है
हर लम्हा कत्ल हो रही इंसानियत वहां
गिनती करें लाशों की वह मशीन कहां है
गैर की जमीं पे ही बसा लिया मुल्क
कहते हैं हम सा दूसरा जमीन कहां है
जो देखता-सुनता है मगर बोलता नहीं
हम जैसा मेरी जां तमाशबीन कहां है
इंसान में गैरत के लिए अब जगह कहां
आंख का पानी भी अब नमकीन कहां है
बच्चे मैं तुझे कल के लिए कैसे दुआ दूं
दुनिया भी तेरी इस कदर हसीन कहां है? ❑

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) अशोक भारत (प्रकाशक), सुरभि प्रिन्टर्स, इंडियन प्रेस कॉलोनी, मलदहिया वाराणसी से मुद्रित तथा सर्व सेवा संघ-परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001, फोन/फैक्स नं. 0542-2440385 से प्रकाशित। संपादक : बिमल कुमार, कार्य.संपादक : अशोक मोती। छपी प्रतियाँ : 1400